● वर्ष-2
● अंक-147
रायपुर, मंगलवार
07 फरवरी 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

उच्च शिक्षा के लिए 30 लाख भारतीय विदेश गये

संसद में दी गई जानकारी, ईडी ने क्रिप्टो मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया, 936 करोड़ जब्त

नई दिल्ली। अडाणी समूह से जुड़े मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने और संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा में लगातार तीसरे दिन कामकाज नहीं हो सका और एक बार के स्थगन के बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी। सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि 2017 से 2022 के दौरान 30 लाख से अधिक भारतीय उच्च शिक्षा के लिए विदेश गये। जनता दल (यू) के सांसद राजीव रंजन सिंह और अन्य सदस्यों के प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा, ''गृह मंत्रालय का आव्रजन ब्यूरो भारतीयों के प्रस्थान और आगमन के आंकड़े रखता है। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए भारतीयों के विदेश जाने की श्रेणी के तहत जानकारी एकत्रित करने का कोई सूचकांक नहीं है। भारतीयों के उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की जानकारी या तो उनकी मौखिक घोषणा के आधार पर या आव्रजन मंजूरी के समय उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये गंतव्य देश के वीजा के प्रकार के आधार पर जुटाई जा सकती है।'' सरकार ने कहा कि 7.50 लाख भारतीयों ने 2022 में विदेश जाने का अपना उद्देश्य अध्ययन या शिक्षा बताया। यह संख्या 2021 में 4.4 लाख, 2020 में 2.59 लाख, 2019 में 5.86 लाख, 2018 में5.17 लाख और 2017 में 4.54 लाख थी।

ईडी ने क्रिप्टो मामले में 936 करोड़ रुपये जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रिप्टो करेंसी से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और 936 करोड़ रुपये जब्त किये हैं। सरकार ने सोमवार को संसद को सूचित किया। इसके अलावा, सरकार ने यह भी बताया कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत, 289.28 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई

है और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ज़नमई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे वज़ीरएक्स के रूप में जाना जाता है, और इसके निदेशकों को क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े 2,790 करोड़ रुपये के लेनदेन के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय क्रिप्टो करेंसी की धोखाधड़ी से जुड़े अनेक मामलों में जांच कर रहा है जिनमें धनशोधनमें भी क्रिप्टो लेनदेन का पता चला है।

तैयार इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बना भारत

इसके अलावा सरकार ने जानकारी दी है कि भारत विश्व में तैयार इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है और वित्त वर्ष 2022 में इसकी खपत 10.6 करोड़ टन थी। इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सोमवार को एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि विश्व में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत लगभग 233 किलोग्राम है जबकि भारत में इसकी प्रति व्यक्ति खपत लगभग 77.2 किलोग्राम है जो विगत आठ वर्षों में 50 प्रतिशत तक बढ़ी है।

कंपनियों को घरेलू एलपीजी बिक्री से हुई बड़ी हानि

सरकार ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की बिक्री से बड़ी हानि हुई है जिसकी भरपाई करने के उद्देश्य से हाल ही में ओएमसीज के लिए 22000 करोड़ रुपये की एकमुश्त रशि स्वीकृत की गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एलपीजी सहित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में संबंधित उत्पादों के मूल्य से जुड़े हैं। तेली ने यह भी बताया कि सरकार ने वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों के लिए 12 रिफिल तक 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम प्रति सिलेंडर की लक्षित राजसहायता शुरू की है।

'परीक्षा पे चर्चा' पर 28 करोड़ रुपये खर्च हुए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ किए जाने वाले संवाद के कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' के पहले पांच संस्करणों पर 28 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। इस कार्यक्रम का छठा संस्करण गत 27 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुआ था। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 2018 में 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम पर 3.67 करोड़ रुपये,2019 में 4.93 करोड़ रुपये, 2020 में 5.69 करोड़ रुपये,2021 में 6 करोड़ रुपये और 2022 में 8.61 करोड़ रुपये खर्च हुए। मंत्री के जवाब में इस साल के आयोजन पर खर्च का ब्योरा नहीं है। इस कार्यक्रम का पहला संस्करण 16 फरवरी, 2018 को को आयोजित हुआ था।

इन दिनों ✍ शशांक शर्मा

विधानसभा का बजट सत्र एक मार्च से

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से प्रारंभ होगा और 24 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 14 बैठकें होंगी, इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। भूपेश बघेल सरकार के लिए चुनाव से पहले का आखिरी बजट इस सत्र में पेश किया जाएगा। बजट को पारित कराना सरकार का मुख्य कार्य होगा। लेकिन चुनाव का माहौल जिस तरह बन रहा है उससे विपक्ष इस सत्र में सरकार को घेरने का भरपूर प्रयास करेगा और सरकार भी आगामी चुनाव को देखते हुए लोक-लुभावना बजट प्रस्तुत करेगी। वैसे तो विधानसभा के 3 प्रमुख सत्र होते है और संविधान में कार्यवाही की एक प्रक्रिया है जिसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल के बाद ध्यानाकर्षण के माध्यम से प्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षक करना होता है। समय के साथ विधानसभा के सत्र की अवधि छोटी होती जा रही है और निर्धारित समय से पहले ही सत्र समाप्त हो रहे है। सदन की कार्यवाही भी आधे दिन से ज्यादा समय स्थगित हो रहे है। बजट सत्र में सरकार की मजबूरी है कि उसे आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट पारित कराना पड़ता है। इस लिहाज से आगामी सत्र की बैठकें मात्र 14 दिन की होंगी तो इसमें बजट पर चर्चा और विभागों की मांगों पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाएगी। ऐसा लगता है कि आगामी सत्र की गरमाहट का आभास सरकार को हो गया है। आगामी सत्र में विपक्ष जहां आरक्षण, धर्मान्तरण, कानून व्यवस्था की बदहाली और प्रदेश में अवरुद्ध विकास कार्य के साथ भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार को घेरेगा। वहीं विधानसभा द्वारा पारित आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाने के मामले पर सत्ता पक्ष भी आक्रमक रहेगा। जैसे भी हो सदन में प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य अवश्य होने चाहिए जिससे जनता की समस्या की चर्चा विधानसभा में हो सके। विपक्ष को भी चाहिए कि सत्र को अधिकाधिक चलाकर विभिन्न माध्यमों से चर्चा के द्वारा सरकार को घेरे। पिछले 3 सत्रों के दौरान यह देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर टिप्पणी करके माहौल को गरमाता है और उकसा कर उन्हें गर्भगृह में आने पर मजबूर करता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की विगत 22 वर्षों से यह विशेषता रही है कि विपक्ष गर्भगृह में आकर कम प्रदर्शन करता है। ऐसा करने पर नियमानुसार स्वमेव निलंबित हो जाते है। यही कारण है कि प्रदेश की विधानसभा में संसदीय कार्य सुचारु रुप से होते रहे है। भारतीय जनता पार्टी के केवल 14 विधायक ही सदन में प्रतिनिधित्व करते है और सत्ता पक्ष के 71 विधायक है। ऐसी स्थिति में भी सत्ता पक्ष को घेरने और जनहित के मुद्दों को सदन में उठाने में विपक्ष भी सक्रिय रहता है, यही संसदीय प्रणाली की विशेषता है।

हाईकोर्ट को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं : राजभवन

रायपुर। हाईकोर्ट द्वारा राज्यपाल के सचिवालय को नोटिस जारी करने के मामले में राजभवन ने बताया है कि उन्हें हाई कोर्ट राज्यपाल को नोटिस जारी नही कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बताया कि 5 जजों की संविधान पीठ ने राष्ट्रपति व राज्यपाल को नोटिस जारी करने पर पूर्णतः रोक लगाई है। गौरतलब है कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई के बाद राज्यपाल सचिवालय को हाईकोर्ट के द्वारा नोटिस जारी की गई थी।

मामला आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 से जपड़ा है जिसमें कुल आरक्षण का प्रतिशत 76 प्रतिशत कर दिया था। दिसंबर आरक्षण संशोधन विधेयक राज्यपाल के

पास पहुंचा पर उन्होंने अब तक इसमें दस्तखत नहीं किया है। इस मामले पर बिलासपुर के अधिवक्ता हिमांग सलूजा व राज्य सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें सुनवाई हुई। राज्य शासन की तरफ से देश के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल हाईकोर्ट में पेश हुए । उनके साथ ही महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा भी राज्य शासन की तरफ से पैरवी कर रहे थे, तो वही अधिवक्ता हिमांग सलूजा की तरफ से सीनियर अधिवक्ता निर्मल शुक्ला व शैलेंद्र शुक्ला पैरवी कर रहे थे।

सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में अधिवक्ताओं ने तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि राज्यपाल को विधानसभा के द्वारा पास विधेयक को 15 दिन तक ही अपने पास रोकने का अधिकार है। इसके बाद या तो उन्हें विधेयक वापस लौट आना पड़ता है या दस्तखत करने पड़ते हैं। पर राज्यपाल ने दोनों में से कोई भी कदम नहीं उठाया। ऐसा नहीं करने पर उन्हें विधेयक को राष्ट्रपति को भेज देना चाहिए था। पर राज्यपाल ने यह भी नहीं किया, जो कि संविधान के अनुच्छेद 200 का पूर्णतः उल्लंघन है। सुनवाई के बाद सिंगल बेंच के द्वारा राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में मामले में जवाब मांगा। शाम होते होते राजभवन ने इसमे स्थिति भी स्पष्ट कर दी। राजभवन से जारी नोट में बताया गया है कि, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने रामेश्वर प्रसाद एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं एक अन्य मामले में फैसला देते हुए न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया था कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को नोटिस जारी करने पर पूर्णतः रोक है, क्योंकि वह किसी न्यायालय के प्रति जवाब देह नहीं है।

अडाणी मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कर रही कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को देशभर में जिला कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में जिले में स्थित एलआईसी और एसबीआई कार्यालयों पर मार्च और विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलवा अडाणी समूह से जुड़े मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने और संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा किया जिसके चलते तीसरे दिन भी कार्यवाही बिना कामकाज के दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी।

प्रमुख समाचार

मोदी सरकार का बजट गरीबों पर गुपचुप स्ट्राइकः सोनिया गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के केंद्रीय बजट पर निशाना

साधा है। उन्होंने आम बजट को गरीबों पर एक गुपचुप स्ट्राइक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे गरीब हो या मध्यम वर्ग, ग्रामीण हो या शहरी, सभी रुपये में आ रही गिरावट और आय में कमी जैसी समस्याओं को झेल रहे हैं। एक अखबार में छपे लेख में सोनिया गांधी ने कहा बजट में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए आवंटन को कम करके स्थिति को और खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा, चार साल में कीमतों में वृद्धि का मतलब है कि रुपया 2018 की तुलना में काफी नीचे गिर गया है। सोनिया गांधी ने कहा, मोदी सरकार के निजीकरण ने राष्ट्रीय संपत्तियों को बहुत ही सस्ते में निजी हाथों में सौंप दिया है, इससे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा, यहां तक कि सरकार एलआईसी और एसबीआई जैसे सार्वजनिक संस्थानों को भी अपने खास दोस्तों के स्वामित्व वाली प्रबंधन कंपनियों में निवेश करने के लिए मजबूर कर रही है।

सबसे बड़ी हेलिकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन, 10 हजार को मिलेगा रोजगार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुमकुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेडकी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित की और विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आध्यात्म, ज्ञान-विज्ञान की महान भारतीय परंपरा को कर्नाटक ने सशक्त किया है। इसमें भी तुमकुरु का विशेष स्थान है। सिद्धगंगा मठ की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। संतों के आशीर्वाद से आज कर्नाटक के युवाओं को रोज़गार देने वाले, ग्रामीणों और महिलाओं को सुविधा देने वाले, देश की सेना और मेड इन इंडिया को ताकत देने वाले, सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। 2014 से पहले के 15 सालों में जितना निवेश एयरोस्पेस सेक्टर में हुआ उसका 5 गुना पिछले 8-9 वर्षों में हो चुका है। आज हम अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार तो दे ही रहे हैं बल्कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि यही एचएएल है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए...आज एचएएल की ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, एचएएल की बढ़ती ताकत बहुत से पुराने झूठों और झूठे आरोप लगाने वालों का पर्दाफाश कर रही है।

कारमेंस टेलीस्कोप की मदद से तलाशी गई 'वोल्फ 1069बी' की पथरीली दुनिया

नई दिल्ली। नए ग्रहों की खोज की दिशा में इंसानों के रहने लायक एक ग्रह मिला है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यहां पर इन्सानी बस्ती बसाई जा सकती है। यह एक पथरीली दुनिया है, लेकिन यहां पानी की अपार संभावनाएं दिख रही हैं। इसलिए उम्मीद है कि इंसान यहां आसानी से रह सकेगा। यह धरती से 1.26 गुना ज्यादा वजनी है और 1.08 गुना बड़ा है। इसे स्पेन के कालार एल्टो ऑब्जर्वेटरी में लगे 11.5 फुट ऊंचे कारमेंस टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया है। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, यह हमारी धरती से महज 31 प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों ने इसे वोल्फ '1069बी' का नाम दिया है। हालांकि, अभी इसके पर्यावरण को समझने में थोड़ा समय लगेगा। दुनियाभर के 50 वैज्ञानिक इसकी खोज में लगे थे। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि यह अपने लाल बौने तारे 1069बी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। 5,200 से अधिक ग्रह खोजे... वैज्ञानिकों ने अब तक 5,200 से ज्यादा ग्रह खोजे हैं, लेकिन सिर्फ 200 रहने लायक हो सकते हैं।

शाही ईदगाह मस्जिद का बिजली कनेक्शन कटा मुकदमा भी दर्ज

नई दिल्ली। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद की बिजली आपूर्ति 5 फरवरी को अवैध बिजली

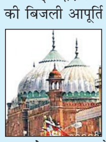

कनेक्शन होने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के साथ काट दी गई। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के सचिव तनवीर अहमद से जुर्माना भी वसूला गया। यहां सरकार द्वारा जारी एक प्रेस बयान के अनुसार, राज्य में अवैध बिजली खपत के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। बयान के मुताबिक, मथुरा जिला पुलिस और बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने कनेक्शन काटा था। इस मामले में कृष्णा नगर थाने में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। बयान के मुताबिक श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। शाही ईदगाह मस्जिद का श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के साथ मस्जिद की संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। मई 2022 में मथुरा की अदालत ने मस्जिद को हटाने की याचिका पर सुनवाई की अनुमति दी थी कि यह

हिंडनबर्ग पर केस किया तो अडानी के पोते लड़ते रहेंगे केस- हरीश साल्वे

नई दिल्ली। भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने अडानी विवाद पर कुछ प्रकाश डाला

और कहा कि कोई भी इससे खुश नहीं है। उन्होंने रेखांकित करते हुए कहा कि भारत अब पश्चिमी देशों की शैडो से बाहर आ गया है और दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इंडिया टुडे से बात करते हुए हरीश साल्वे ने कहा कि कोई भी इस बात से खुश नहीं है कि भारतीय कारोबारी दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वरिष्ठ वकील ने कहा कि एक समय था जब हम ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित कर रहे थे। अब मैं देख रहा हूं कि ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन में निवेश के लिए भारतीयों को लुभा रही है। यह दुनिया की गतिशीलता में एक मात्रा परिवर्तन रहा है और इसके नतीजे होने ही थे। साल्वे ने यह भी कहा कि गौतम अडानी के खिलाफ लगाया गया आरोप भारत और भारतीयों पर एक थोक हमला है। आपके पास अनुमानित राजस्व है क्योंकि आपके पास एक नियामक है जो आपके टैरिफ को ठीक कर रहा है.. आप बहुत पैसा नहीं कमा सकते हैं।

मोहन भागवत के पंडित शब्द का उल्लेख किए जाने पर हो रहा बेवजह विवाद

गौतम मोरारका

मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख भागवत ने यह भी कहा कि सत्य ही ईश्वर है। उन्होंने कहा कि जाति की श्रेष्ठता की कल्पना में ऊंच-नीच में अटक कर हम गुमराह हो गए हैं और इस भ्रम को दूर कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं।

आजकल एक सिलसिला-सा चल पड़ा है कि समाज में जाति और धर्म के आधार पर भ्रम और भय का माहौल बनाया जाये। इसके लिए प्रमुख लोगों के संबोधनों के अलग-अलग मायने निकाल कर उसे प्रस्तुत किया जाता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में एक कार्यक्रम में मराठी में जो संबोधन दिया उसका आशय यह निकाला गया कि उन्होंने समाज में जाति व्यवस्था बनाने के लिए पंडितों को जिम्मेदार ठहराया है। जबकि पंडित शब्द से उनका आशय %विद्वानों% से था। इस नकारात्मक चलन को देखते हुए समाज के प्रमुख लोगों को भी अपने संबोधनों के दौरान और सावधानी बरतने की जरूरत है।

दूसरी ओर, चुनावों को निकट देखते हुए बेरोजगारी के मुद्दे को विपक्ष जोरशोर से उठा रहा है तो वहीं जाति से जुड़े मुद्दे भी आजकल खूब उठाये जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाये जा रहे हैं तो जातिगत मुद्दों पर सत्तारुढ़ दल से जुड़े लोगों का कहना है कि जो लोग ऐसी बातें कह रहे हैं वह हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं। इसी सब विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है। मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि श्रम के प्रति सम्मान की भावना की कमी देश में बेरोजगारी के मुख्य कारणों में से एक है। साथ ही संघ प्रमुख भागवत ने लोगों से सभी तरह के काम का सम्मान करने और नौकरियों के पीछे भागना बंद करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं कहा जा सकता।

मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते

हुए संघ प्रमुख भागवत ने यह भी कहा कि सत्य ही ईश्वर है। उन्होंने कहा कि जाति की श्रेष्ठता की कल्पना में ऊंच-नीच में अटक कर हम गुमराह हो गए हैं और इस भ्रम को दूर कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि समाज के बंटवारे का फायदा हमेशा दूसरों ने उठाया है इसीलिए हमारे देश पर आक्रमण भी हुए। उन्होंने कहा कि समाज बंटा रहा इसी वजह से बाहर देश से आए लोगों ने हमारे देश पर राज किया। मोहन भागवत ने कहा कि जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंचा, कोई नीचा या कोई अलग कैसे हो सकता है? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक हैं। उनमें कोई जाति, वर्ण नहीं है लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई जोकि गलत था।

संघ प्रमुख ने कहा, ''इस्लामी आक्रमण से पूर्व अन्य हमलावरों ने हमारी जीवनशैली, हमारी परंपराओं एवं चिंतन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया। लेकिन मुस्लिम हमलावरों का एक तर्क था- पहले, उन्होंने हमें अपनी ताकत के दम पर पराजित किया और फिर उन्होंने हमें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दबाया।'' इसके अलावा संघ प्रमुख ने कहा कि समाज में व्याप्त अस्पृश्यता का संतों और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जैसे जानेमान लोगों ने विरोध किया। आरएसएस प्रमुख ने कहा, ''अस्पृश्यता से परेशान होकर, डॉ. आंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ दिया लेकिन उन्होंने किसी अन्य धर्म को नहीं अपनाया और गौतम बुद्ध द्वारा दिखाए गए मार्ग को चुना। उनकी शिक्षाएं भारत की सोच में भी बहुत गहराई तक समाई हुई हैं।

मोहन भागवत ने मराठी में दिये गये अपने संबोधन में कहा है कि लोग चाहे किसी भी तरह का काम करें, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि काम के लिए चाहे शारीरिक श्रम की आवश्यकता हो या बुद्धि की, चाहे इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता हो या 'सॉफ्ट' कौशल की- सभी का सम्मान किया जाना चाहिए।'' उन्होंने कहा, ''हर कोई नौकरी के पीछे भागता है।

सरकारी नौकरियां केवल करीब 10 प्रतिशत हैं, जबकि अन्य नौकरियां लगभग 20 प्रतिशत हैं। दुनिया का कोई भी समाज 30 प्रतिशत से अधिक नौकरियां उत्पन्न नहीं कर सकता।'' उन्होंने कहा कि जिस काम में शारीरिक श्रम की जरूरत होती है, उसे अब भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। भागवत ने कहा कि जब कोई जीविकोपार्जन करता है, तो समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि जब हर काम समाज के लिए हो रहा है तो वह छोटा या बड़ा अथवा एक-दूसरे से अलग कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की दृष्टि में हर कोई समान है और उसके सामने कोई जाति या सम्प्रदाय नहीं है। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि विश्व में स्थिति देश के 'विश्वगुरु' बनने के अनुकूल है। उधर, मोहन भागवत के बयान पर राजनीतिक बवाल भी शुरू हो गया है। शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सांसद संजय राउत ने कहा है कि मोहन भागवत द्वारा कही गई बातें समाज में एकता रखने के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि समाज तोड़ने का काम कौन कर रहा है? संजय राउत ने कहा कि यह काम आपके लोग ही कर रहे हैं इसलिए यह बात आप पहले उन्हें समझाइये जो सत्ता में बैठे हुए हैं। वहीं निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर तंज कसा है जिसमें उन्होंने लोगों से नौकरियों के पीछे नहीं भागने का आग्रह किया था। सिब्बल ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हर साल दो करोड़ नौकरियां देने के वादे का क्या हुआ।

रेल बजट में केंद्र सरकार ने बस्तर संभाग को दी अनेकों सौगातें : राणा

जगदलपुर। भाजपा शहर महामंत्री संग्राम सिंह राणा ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने आम बजट रेल 2023- 2024 मे बस्तर संभाग से दूसरे राज्यों को रेल लाइन से जोडने् प्रस्तावित 6 नई पुरानी परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण कार्य आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। केंद्र सरकार ने नारायणपुर से दंतेवाड़ा 100 किलोमीटर की प्रस्तावित नई रेल लाइन के लिए रेल बजट में प्रस्ताव पारित किया है। इसके अलावा दक्षिण बस्तर में रेल लाइनों के सर्वेक्षण भी प्रस्तावित किए गए हैं। रेल बजट में जगदलपुर रेलवे स्टेशन के लिए यात्री सुविधाओं को बढ़ाने हेतु 10 करोड़ का प्रावधान रेल बजट में किया गया है। भवन के जीर्णोद्धार और विस्तार पर रेलवे लगभग 10 करोड़ खर्च करेगा।

केंद्र सरकार ने पिछले रेल बजट मे मलकानगिरी सुकमा दंतेवाड़ा, किरंदुल मनगुरु, किरंदुल बीजापुर पटनम प्रस्तावित रेल लाइनें हैं। रेल बजट में नारायणपुर से दंतेवाड़ा 100 किलोमीटर, बीजापुर से वारंगल 218 किलोमीटर, राज महेंद्री से कोंटा 250 किलोमीटर, किरंदुल से बीजापुर 83 किलोमीटर, सुकमा कोंटा भद्राचलम 146 किलोमीटर एवं दल्ली राजहरा से बालोद धमतरी 130 किलोमीटर का सर्वेक्षण कार्य को आगे बढ़ाने की योजना इस रेल बजट में तय की गई है।

रेल बजट में केके रेल लाइन दोहरीकरण के लिए बस्तर को आंध्रप्रदेश से जोडने् वाली किरंदुल-कोत्तावालसा रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए राशि का प्रावधान बजट में किया गया है जिसमें किरंदुल से जगदलपुर 150 किलोमीटर के लिए 135 करोड़, जगदलपुर से कोरापुट 110 किलोमीटर के लिए 170 करोड और कोरापुट से कोट्टावालसा के लिए 410 करोड़ों के बजट में दिए गए हैं।

राणा ने कहा कि 1965-66 में जगदलपुर रेलवे भवन का निर्माण किया गया था लेकिन कांग्रेस ने 50 साल केंद्र में शासन करने के बाद भी जगदलपुर भवन की सुध नहीं ली। कांग्रेस की सरकार ने मात्र एक ट्रेन की सुविधा बस्तर को दिया गया था। 2011-12 के भारतीय जनता युवा मोर्चा के रेल आंदोलन ने आज 5 यात्री ट्रेनों की सुविधा बस्तर वासियों को मिली है।

बजट में टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर दिया गया बल : मनोहर

नगरी। भाजपा मंडल बेलर (सिहावा) के महामंत्री मनोहर दास मानिकपुरी ने बजट पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि इस बजट के आधार पर भारत नए संकल्पों को लेकर आगे बढ़ेगा। केंद्रीय बजट में निम्न और मध्यम वर्ग के लिए अनेकों सौगातें दी गई है। इस बजट में टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बल दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है जिससे सड़कें, रेल, पोर्ट के क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित होने से भारत के विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे साथ ही देश की बड़ी आबादी को आय के नए अवसर प्राप्त होंगे। मनोहर दास मानिकपुरी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये आगे कहा कि बजट में वित्तमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 66 प्रतिशत की कच्चे मकानों में रहने वाली गरीब जनता के लिए बहुत बड़ा उपहार है गरीबों के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट में किया गया प्रावधान स्वागत योग्य है। मानिकपुरी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये आगे कहा कि बजट मे करमुक्त आय की सीमा को बढ़ाकर तीन लाख किए जाने और सात लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं लगने का प्रावधान मध्यमवर्गीय लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात अमृत काल का यह प्रथम बजट देश के विकास की नई गाथा शुरू करेगा।मनोहर दास मानिकपुरी ने कहा कि पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण का लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए करने से देश के किसान वर्ग को सबसे अधिक लाभ पहुंचेगा और किसान फसल उत्पादन के लिए अपने वित्त की आवश्यकता को आसानी से ऋण द्वारा पूरा कर सकेंगे और देश के विकास में अपना और अधिक योगदान दे सकेंगे।

जनजातीय समूहों के विकास के लिए पहली बार अलग से बजट में प्रावधान : महेन्द्र नेताम

नगरी। भाजपा अजजा मोर्चा के जिलाध्यक्ष महेन्द्र नेताम ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वाकई यह अमृत काल का बजट है। पहली बार जनजातीय समूहों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके। अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। अगले तीन साल में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापकों व सहयोगी स्टाफकी नियुक्ति की जाएगी। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन शुरू किया जाएगा। इस बजट की सात प्राथमिकताएं हैं, जो सप्तऋषि की तरह अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करेंगी। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी को बधाई देते हैं।

12 को बस्तर आएंगे जेपी नड्डा

जगदलपुर। भारतीय जनता पार्टी तोकापाल मण्डल कार्यसमिति की बैठक बड़े मोरठपाल में हुई जिसमें तोकापाल मण्डल में 14 शक्ति केंद्र व 70 बूथ है, जिसमें सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, बूथ पालकों से चर्चा की गई और आगामी चुनाव को लेकर गहन चिंतन किया गया। सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी अपने - अपने बूथ पर सक्रिय रूप से कार्य पर जुट जांऐ और पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचने में लग जाएं। कार्यसमिति की बैठक में 12 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बस्तर आगमन हो रहा है, इस पर भी चर्चा किया गया। बैठक में बस्तर जिलाध्यक्ष रूपसिंह मण्डावी, किरण देव, पूर्व विधायक बैदू राम कश्यप, लच्छूराम कश्यप, मण्डल अध्यक्ष विनायक गोयल, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष लछिन यादव, वेदप्रकाश पाण्डेय, बाबुल नाग, रैतू राम बघेल, जीवनाथ मौर्य, सुभाष कश्यप, रितेश दास जोशी, सोमवार कश्यप, परदेशी कश्यप, दशरथ बघेल, महिला मोर्चा अध्यक्ष रैयमती बघेल पदमनी कश्यप, शांति नाग, बसंती कश्यप, सनमती राणा, और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहें।

एलआईसी भवन के सामने कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन

राजनांदगांव। अमरीकी फर्म हिँडनबर्ग द्वारा अडानी समूह की वित्तीय अव्यवस्थाओं का खुलासा होने के बाद देश भर में कोहराम मचा हुआ है। इस बीच सोमवार को केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए रेल्वे स्टेशन रोड स्थित एलआईसी भवन के सामने कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार पर आम लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे को एक उद्योगपति के हाथों सौंपने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि एलआईसी और एसबीआई में आम आदमी से लेकर उद्योगपतियों ने निवेश किया है। यह दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री अड़ानी को आर्थिक रूप से बढ़ाने के लिए अनैतिक आधार पर लोगों की खून पसीने की कमाई को सौंप दिया। अड़ानी मामले में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए । हिंडनबर्ग फर्म द्वारा किए गए खुलासे को लेकर महापौर ने कहा कि इसमें और देरी होती तो देश की आर्थिक हालत बद से बदतर हो सकती थी। उधर एसबीआई के ब्रांच के सामने भी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा ने आम जनता के पैसे को डुबाने के लिए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। धरना देने वालों में प्रमुख रूप से श्रीकिशन खंडेलवाल, सूर्यकांत जैन, राजेश चौहान, शारदा तिवारी, आसिफ अली, अशोक फडनवीस, महेश साहू, अमित चंद्रवंशी, विनय झा, मैहुल मारू, नरेश शर्मा, दुलारी साहू, समेत अन्य लोग शामिल थे।

13 को गंगानगर में विस्थापन पीड़ितों की संघर्ष सभा

राकेश टिकैत, बादल सरोज सहित कई नेता करेंगे संबोधित

कोरबा। 13 फरवरी को कोरबा जिले के बांकी मोंगरा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ किसान सभा की अगुआई में श्विस्थापन पीड़ितों की संघर्ष सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस सभा को संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत, अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव बादल सरोज, बीकेयू के महासचिव राजवीर सिंह जादौन, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला तथा छत्तीसगढ़ किसान सभा के सचिव संजय पराते सहित कई राष्ट्रीय और स्थानीय नेता संबोधित करेंगे।

छग किसान सभा के जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा कि संघर्ष सभा में हजारों किसान हिस्सा लेंगे और केंद्र की मोदी सरकार और राज्य में भूपेश सरकार की किसानों और आदिवासियों को विस्थापित करने वाली नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। यह संघर्ष सभा गंगानगर में 13 फरवरी की शाम 5 बजे आयोजित की जा रही है। हसदेव-सरगुजा क्षेत्र के किसानों के महासम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद टिकैत यहां किसान सभा द्वारा आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि हाल ही में किसान सभा के केरल में हुए राष्ट्रीय महाधिवेशन को संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत संबोधित करने आये थे, तब उन्होंने उनसे मिलकर कोरबा जिले के विस्थापितों की समस्याओं के बारे में बातचीत की थी तथा उन्हें कोरबा आमंत्रित किया था।

उल्लेखनीय है कि कोरबा जिले में एसईसीएल द्वारा विस्थापित ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर और आदिवासी वनाधिकार से जुड़े मुद्दों पर किसान सभा का लगातार अभियान-आंदोलन चल रहा है। कुसमुंडा में भू-विस्थापितों को रोजगार देने के सवाल पर लगातार 465 दिनों से धरना जारी है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्वासित गांवों में बुनियादी मानवीय सुविधाओं को प्रदान करने की मांग पर कई बार खदान बंदी भी हुई है और वन भूमि पर काबिज आदिवासियों को वनाधिकार देने की मांग पर हाल ही में मुख्यमंत्री के आगमन पर प्रदर्शन भी आयोजित किया गया है।

किसान सभा नेता ने कहा कि आज कोरबा जिला देश के सबसे प्रदूषित जिलों में से एक है। एनटीपीसी और अन्य प्लांटों द्वारा अनियमित तरीके से जो राखड़ बांध बनाये गए हैं, उससे किसानों की खेती-किसानी स्थायी रूप से बर्बाद हुई है और आम जनता के स्वास्थ्य पर इतना खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है कि लोगों की औसत आयु घटकर आधी हो गई है। इसके खिलाफ भी किसान सभा प्रभावित किसानों को संगठित कर रही है।

उन्होंने कहा कि इन आंदोलनों को ग्रामीण जनता का भारी समर्थन भी मिला है। इन मुद्दों पर जगह-जगह हो रहे आंदोलन से प्रशासन की कई बार किरकिरी भी हुई है। टिकैत के आने से विस्थापन के खिलाफ और केंद्र व राज्य सरकार की किसान विरोधी और आदिवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ हो रहे आंदोलनों को और बल मिलेगा। किसान सभा नेता ने बताया कि टिकैत के स्वागत और संघर्ष सभा के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू हो चुकी है। पूरे जिले में चार दिनों के लिए पांच वाहन जत्थे निकाले जाएंगे, जो गांवों में सभाओं, बैठकों और पर्चा वितरण के जरिये संघर्ष सभा और इससे जुड़े मुद्दों का व्यापक प्रचार करेंगे, ताकि खेती-किसानी, विस्थापन और भूमि से जुड़े मुद्दों पर किसान सभा के दृष्टिकोण और साझा संघर्ष विकसित करने की जरूरत के संदेश को आम जनता तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही आम जनता के मुद्दों पर ईमानदारी के साथ संघर्ष कर रहे सभी छोटे-बड़े संगठनों को इस मंच पर संगठित करने की कोशिश की जा रही है।

कोयला में अब 15 रुपए सेस लगाने सीएमपीएफ बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला

कोरबा। कोयला कर्मियों के कोल माइंस प्राविडेंट फंड सीएमपीएफ की स्थिति सुधारने के लिए कोयला में लगाए जा रहे 10 रुपए के सेस को बढ़ा कर 15 रुपए किया जाएगा। साथ ही 10 साल से कम की नौकरी वाले कर्मियों के आश्रितों को भी पेंशन का लाभ देने व पेंशन बढ़ोतरी पर पूर्व की इंवेस्टमेंट कमेटी को संपूर्ण जांच कर रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।

साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड एसईसीएल सहित कोल इंडिया की अन्य संबद्ध कंपनियों में कार्यरत कर्मियों के वेतन से निश्चित राशि की कटौती कर सीएमपीएफ में जमा की जाती है और इतनी ही राशि प्रबंधन जमा करता है। सेवानिवृति के बाद कर्मियों को इस राशि से ही पेंशन प्रदान की जाती है। सीएमपीएफ बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय लेकर दिल्ली में सीएमपीएफ बोर्ड आफ ट्रस्टी की 175वीं बैठक कोयला सचिव अमृतलाल मीना की अध्यक्षता में हुई। इसमें सभी संगठन के बोर्ड आफट्रस्टी मेंबर, निदेशक कार्मिक सीआइएल विनय रंजन, सभी कंपनी के निदेशक कार्मिक और सीएमपीएफ कमिश्नर विजय मिश्रा उपस्थित रहे।

बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर निराकरण का आदेश जारी किया गया हुई। इसमें प्रमुख रूप से सेस बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर कोयला सचिव मीना ने 15 रूपए प्रति टन के रूप में जल्द मंजूरी मिलने का आश्वासन दिया। साथ आवश्यकता पड़ने पर जल्द ही 20 रूपए प्रति टन करने पर सहमति बनी। सीआईएल प्रबंधन द्वारा जानकारी दी गई कि अब से ठेका कर्मियों के कांट्रैक्ट एनआइटी में सुधार कर माइनिंग में कार्य करने वाले सभी ठेका कर्मियों का सीएमपीएफ में ही अकाउंट खोलना अनिवार्य किया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि नियमित रूप से सीएमपीएफ इंस्पेक्टर कोयला उद्योग में कार्यरत सभी ठेका कर्मियों की जानकारी लेंगे और उनके सीएमपीएफ खाते की समय-समय पर जांच करेंगे। इसी तरह ठेका कर्मियों व कोयला कामगारों के सीएमपीएफ की समस्याओं का निराकरण के लिए कंपनी में दौरा करेगी।

छत्तीसगढ़
प्रमुख समाचार

महानदी मैया की महाआरती में शामिल हुए मुख्यमंत्री

राजिम। माघी पुन्नी मेला के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सबसे पहले भगवान श्री राजीव लोचन मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन कर प्रदेश के खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन उपरांत मुख्यमंत्री जी सीता बाड़ी का अवलोकन करने पहुंचे। यहां की भव्यता देख सीएम बघेल काफी गदगद हुए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने महानदी मैया की महाआरती में शामिल होकर विधि विधान के साथ आरती उतारी। श्री बघेल ने जैसे ही आरती के पात्र घुमाना शुरू किया आलौकिक दृष्य उभरकर सामने आया। उपस्थित पंडितों ने मंत्रोचार किया। सबसे पहले शंख ध्वनि हुई पश्चात आरती के बाद परिक्रमा किया गया। मुख्यमंत्री ने त्रिवेणी मैया से प्रदेश की खुशहाली के लिए याचना किया। इस मौके पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, राजिम विधायक अमितेष शुक्ल, अभनपुर विधायक धनेन्द्र साहू, सिहावा विधायक लक्ष्मी ध्रुव, शैलेन्द्र साहू, भावसिंह साहू, विकास तिवारी, पद्मा दुबे, प्रीति पाण्डे सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं धर्ममयी श्रद्धालुगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

11 फरवरी को कोरबा जिले में नेशनल लोक अदालत

कोरबा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के अध्यक्ष, जिला न्यायाधीश डीएल कटकवार ने कहा है कि 11 फरवरी को कोरबा एवं जिले के अन्य न्यायालयों में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत में पक्षकार आपसी राजीनामा योग्य मामलों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में निपटारा कर सकते हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक पीडब्ल्यूडी रामपुर, कोरबा में विधिक जागरूकता शिविर के दौरान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरीश चंद्र मिश्र ने उक्त जानकारी दी। मिश्र ने जागरूकता शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को बाल श्रम शिक्षा का अधिकार, लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण, टोनही प्रताड़ना, गुड टच-बैड टच एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा की विधिक सेवा संबंधी अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बालक हो या बालिका, कानून में सबको शिक्षा का समान अधिकार मिला हुआ है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में न्याय से वंचित ना रहे।

लैब टेक्नीशियन की सीधी भर्ती हेतु काउंसिलिंग 13 को

कांकेर। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग से परीक्षा उपरांत मेरिट सूची जारी किया गया था। चयन समिति द्वारा दावा-आपत्ति निराकरण उपरांत मेरिट सूची जारी किया गया है, जिसमेंलैब टेक्नीशियन की भर्ती हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर में 13 फरवरी को प्रातः 10 बजे से काउंसलिंग का आयोजन किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए कांकेर जिले के वेबसाईट www.kanker.gov.in अथवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर की वेबसाईट www.gmckanker.in में डाउनलोड कर अभ्यर्थी मेरिट सूची का अवलोकन कर सकते हैं। उक्त काउंसलिंग में मेरिट सूची के पात्र अभ्यर्थी समस्त मूल दस्तावेजों एवं उनकी दो सेट स्व-प्रमाणित छायाप्रति तथा 01 नवीन फोटोग्राफ के साथ उक्त प्रोफार्मा को भरकर काउंसिलिंग तिथि को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। काउंसिलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया हेतु अपात्र कर दिया जावेगा।

ऑन लाईन सट्टा पर पुलिस की सर्जिकल स्ट्राईक, 9 गिरफ्तार

दुर्ग। जिले में महादेव एप्प ऑन-लाईन सट्टा एप्प द्वारा चलने की सूचना मिलने पर एण्टी क्राईम सायबर युनिट एवं दुर्ग पुलिस की संयुक्त टीम साक्ष्य एकत्रित किया और एक टीम को उत्तरप्रदेश भेजा गया और एलेस्टोनिया अपार्टमेन्ट ग्रेटर नोएडा के 9वी मंजिल से 9 आरोपियों को गिरफ्तारी किया और उनके पास से 3 नग लेपटॉप, 15 नग मोबाईल, एटीएम कार्ड एवं अन्य दस्तावेज जप्त किया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में लॉयन बुक-15 नाम के ब्रांच में 5 पैनल का संचालन हो रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा के एक फ्लैट में दुर्ग-भिलाई के व्यक्तियों द्वारा ऑन-लाईन सट्टा महादेव एप्प के संचालन की सूचना प्राप्त हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) संजय ध्रुव, नगर पुलिस अधीक्षक (दुर्ग) वैभव बैंकर (भापुसे), उप पुलिस अधीक्षक (अपराध) के. के. बाजपेयी के मार्गदर्शन में एण्टी क्राईम एण्ड सायबर यूनिट प्रभारी निरीक्षक संतोष मिश्रा एवं थाना प्रभारी दुर्ग निरीक्षक एस.एन. सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.) के लिये रवाना की गई।

बिलासपुर में वंदे भारत पर फिर हुआ पथराव, कोच का शीशा टूटा, मचा हड़कंप

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार सुबह एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस पथराव का शिकार हुई। चलती ट्रेन पर पथराव होने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। इससे कुछ कोच की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। जानकारी अनुसार आज जब वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर के दाधापारा के पास से गुजर रही थी, तब कुछ शरारती तत्वों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया। पथराव के चलते यात्रियों में हड़कंप मच गया। लोग अपनी सीटों से नीचे हो गए कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अब तक पथराव में 5 कोच के 9 विंडो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई

■ **आरक्षण पर राज्यपाल सचिवालय को नोटिस, 2 सप्ताह में मांगा जवाब**

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से हाईकोर्ट में पहुंच गया है। राज्य सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा गया है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया। उन्होंने कहा कि, राज्यपाल को विधेयक रोकने का अधिकार नहीं है। मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच में हुई है।

दरअसल, विधानसभा में आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद से ही राज्यपाल ने रोक रखा है। इसे न तो सरकार को लौटाया गया और न ही इस पर राज्यपाल ने अब तक हस्ताक्षर ही किए हैं। इसे लेकर राज्य सरकार अब हाईकोर्ट पहुंच गई है। सरकार की ओर से कहा गया कि राज्यपाल की ओर से इस पर हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है, जो अनुच्छेद 200 का उलंघन है। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और महाअधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने पैरवी की है। कोर्ट से बाहर आने के बाद अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि, बिल दिसंबर में पास हुआ था, अब फरवरी हो गया है। अब तक राज्यपाल ने कोई कदम नहीं उठाया है। संविधान के मुताबिक, इस पर अनुमति दें या न दें या फिर राष्ट्रपति को भेजें। राज्यपाल ने कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए हम यहां आए हैं। यह असंवैधानिक है या नहीं, से कोर्ट तय करेगी। इसमें राज्यपाल को देर नहीं करनी चाहिए। यह छत्तीसगढ़ की जनता खासकर आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

राज्य सरकार ने दो दिसंबर को विधानसभा में विधेयक पारित कर आरक्षण 50 से बढ़ाकर 76त्न कर दिया। इस बिल को राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा था, लेकिन अब तक सरकार को वापस नहीं मिला है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारे में भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। पोस्टर वॉर भी चली। अब मामला राज्य सरकार हाईकोर्ट में ले गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि राज्यपाल बिल पास करें या वापस करें। फिलहाल इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।

दरअसल, अधिवक्ता हिमांग सलूजा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 18 जनवरी 2012 को आरक्षण एससी वर्ग के लिए 12, एसटी के लिए 32 और ओबीसी के लिए 14 प्रतिशत किया था। जिसे हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद सरकार ने जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रतिशत 76 फीसदी कर दिया।

दुर्गापुर के 47 घरों तक पहुंची पेयजल की सुविधा

कोरिया। प्रत्येक परिवार को गुणवत्तायुक्त पेयजल की उपलब्धता जिला मुख्यालय से लगभग 18 किमी दूर विकासखण्ड बैकुंठपुर के ग्राम पंचायत उमझर का आश्रित गांव दुर्गापुर पंडो जनजाति बाहुल्य ग्राम है। वनवासी जीवन शैली के परिचायक दुर्गापुर गांव में जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक परिवार को गुणवत्तायुक्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना चुनौतीपूर्ण रहा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के कार्यपालन अभियंता ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में जिले में योजना का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जहां चाह, वहां राह को आदर्श सूत्र मानते हुए दुर्गापुर के प्रत्येक परिवार को जल जीवन मिशन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण पानी उपलब्ध कराने का संकल्प लेकर कार्ययोजना बनाई गई और अंत में ग्रामवासियो के चेहरे पर मुस्कान योजना के फलीभूत होने का प्रमाण खुद ही दे रही है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीणों को जागरूक करने महिलाओं को जल वाहिनी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता है। जल जीवन मिशन के तहत जल वाहिनी रामकुमारी सारथी ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीने के पानी की जांच की जाती है जिससे जल की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त होती है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जल जीवन मिशन के माध्यम से दुर्गापुर के खालपारा और ईबलपारा में 35.78 लाख रुपये की लागत से 47 की संख्या में चिन्हित घरों में नल के माध्यम से गुणवत्तायुक्त पेयजल पहुंचाने का पुनीत कार्य किया जा रहा है। जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से जल पहुंचने से घर तक शुद्ध पेयजल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हो रही है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

त्रिपुरा में अमित शाह ने विरोधियों पर किया हमला

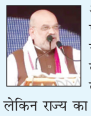

अगरतला। त्रिपुरा की रैली में भाजपा नेता अमित शाह ने जमकर विरोधियों पर हमला किया। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहां कांग्रेस और वाम दलों ने 50 साल तक शासन किया लेकिन राज्य का विकास नहीं हुआ। जबकि हमने 4 लाख परिवारों को घर में पीने का पानी दिया। वामपंथी भाइयों ने 27 साल के अपने शासन में केवल 24 हजार परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाया था। आगे अमित शाह ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि राज्य में एक बार फिर से भाजपा कि सरकार बने तो कमल का बटन दबाइए। वामपंथियों ने आपको अंधकार दिया था हमने आपको विकास दिए हैं, हमने विनाश की जगह विकास और विवाद की जगह विश्वास दिया है। अब यहां सुरक्षा का वातावरण सुनिश्चित हो रहा है। भाजपा नेता ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने राज्य में कैडर राज और टोला बाजी की परंपरा को समाप्त कर त्रिपुरा को विकास की राह पर आगे बढ़ाने का काम किया है।

दिल्ली मेयर का चुनाव हंगामे के कारण तीसरी बार टला

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव नतीजों के बाद सोमवार को तीसरी बार मेयर चुनाव का आयोजन किया गया। इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद मौजूद थे। पिछली दो बैठकों के हंगामे के बाद सोमवार को उम्मीद जताई जा रही थी कि दिल्ली नगर निगम में मेयर के चुनाव से पहले ही सदन में पार्षदों ने जबरदस्त हंगामा कर दिया, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। इससे पहले दो बार मेयर चुनाव में पार्षदों के हंगामे के बाद पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया था। इसके कारण मेयर चुनाव अभी तक नहीं पाया है। ऐसे में सोमवार को तीसरी बार सदन में बैठक बुलाई गई है लेकिन कार्यवाही शुरू होने से पहले ही दोनों पार्टियों के बीच एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है।

भाजपा के आरोपों पर शशि थरूर का पलटवार

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के निधन के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक ट्वीट किया था जिस पर खूब विवाद हुआ था। मुशर्रफ के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए थरूर ने उन्हें शांति की वास्तविक ताकत बताया था। थरूर के ट्वीट के बाद भाजपा उन पर हमलावर हुई थी और कहा था कि कांग्रेस और उसके नेताओं का रवैया हमेशा ही पाक हितैषी रहता है। शशि थरूर के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी नाराजगी जताई थी। अब भाजपा नेताओं के हमले पर थरूर ने पलटवार किया है। एक टीवी कार्यक्रम के दौरान थरूर ने कहा कि मुझे इतिहास सिखाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा, जब किसी का देहांत होता है तो हम उसकी बुरी और अच्छी सारी चीजें याद रखते हैं। इसके अलावा थरूर ने ट्वीट करके कहा, बीजेपी सरकार ने करगिल युद्ध के 4 साल बाद पाकिस्तान के साथ शांति बहाल के लिए बातचीत की थी। 2004 में वाजपेयी-मुशर्रफ ने हाथ मिलाकर एक संयुक्त बयान भी जारी किया। क्या तब मुशर्रफ शांति के लिए विश्वसनिय सहयोगी थे?

कांग्रेस ने एलआईसी-एसबीआई दफ्तरों के बाहर किया प्रदर्शन

नई दिल्ली। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और अदाणी समूह से जुड़े मामले को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देशभर में प्रदर्शन किया। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जीवन बीमा निगम के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर समेत देशभर में विरोध प्रदर्शन किया। संसद का बजट सत्र गत मंगलवार यानी 31 जनवरी को शुरू हुआ था। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा। 14 फरवरी से 12 मार्च तक सदन की कार्रवाई नहीं होगी। इस दौरान विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियां अनुदान मांगों की समीक्षा करेंगी और अपने मंत्रालयों और विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा।

गरीबों पर मोदी सरकार का 'गुपचुप प्रहार' : सोनिया गांधी

नईदिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले दिनों वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जिसपर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सोमवार को कहा कि मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के माध्यम से गरीबों पर 'गुपचुप प्रहार' किया है और समान विचारधारा वाले लोगों को एक साथ आकर सरकार के 'नुकसान पहुंचाने वाले कदमों' का विरोध करना चाहिए तथा वह बदलाव लाना चाहिए जो जनता देखना चाहती है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में अडाणी समूह से जुड़े प्रकरण का भी परोक्ष रूप से हवाला दिया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री 'विश्व गुरु' और 'अमृतकाल' की डींगे हांक रहे हैं जबकि उनके 'चहेते और कृपापात्र व्यवसायी' को लेकर 'वित्तीय धांधली' का मामला सामने आ गया है।

इंडिया एनर्जी वीक 2023 में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

आंतरिक लचीलेपन के कारण भारत ने सभी चुनौतियों को किया पार

बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सोमवार को इंडिया एनर्जी वीक 2023 इवेंट में इंडियन ऑयल द्वारा विकसित सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन-कुकटॉप मॉडल का अनावरण किया। पीएम मोदी ने कहा, हम सभी तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप को देख रहे हैं। कई लोगों के मरने और नुकसान की भी खबर है। तुर्की के पास के देशों में भी नुकसान की आशंका है।

उन्होंने ये भी कहा, भारत के 140 करोड़ लोगों की सहानुभूति सभी भूकंप प्रभावित लोगों के साथ है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि भारत भूकंप प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि बेंगलुरु प्रौद्योगिकी, प्रतिभा और नवाचार की ऊर्जा से भरा शहर है। मेरी तरह आप भी यहां की युवा ऊर्जा को महसूस कर रहे होंगे।

अपनी बात को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भारत के जी20 प्रेसीडेंसी कैलेंडर में पहली बड़ी ऊर्जा घटना है। मैं भारत ऊर्जा सप्ताह कार्यक्रम में सभी का स्वागत करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि 21वीं सदी में दुनिया के भविष्य को तय करने में ऊर्जा क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका निभाता है। भारत आज ऊर्जा के नए संसाधनों के विकास और ऊर्जा परिवर्तन में सबसे मजबूत आवाजों में से एक है।

पीएम मोदी ने कहा कि विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के साथ चल रहे भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2023 के लिए विकास प्रक्षेपण जारी किया। प्रक्षेपण में कहा गया है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। महामारी और युद्ध के प्रभाव के बावजूद भारत 2022 में एक वैश्विक उज्ज्वल स्थान बना रहा।

उन्होंने आगे कहा कि बाहरी परिस्थितियां जो भी हों, आंतरिक लचीलेपन के कारण भारत ने सभी चुनौतियों को पार कर लिया। इसके पीछे कई कारक थे। 1) स्थिर, निर्णायक सरकार, 2) निरंतर सुधार और 3) जमीनी स्तर पर सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण। वहीं, इंडिया एनर्जी वीक 2023 इवेंट में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, हम एक निवेश-अनुकूल ईवी नीति लाए हैं। कर्नाटक इथेनॉल का एक उच्च उत्पादक है।

उन्होंने आगे कहा, हमारा 2025 तक इथेनॉल का 20 प्रतिशत मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य है। पीएम और हमारा अंतिम नारा न्यूनतम उत्सर्जन के साथ अधिकतम शक्ति है। कर्नाटक अक्षय ऊर्जा द्वारा उत्पादित 50,000 मेगावाट के साथ भारत में सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा निर्माता है। कर्नाटक में देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन और ईवी यात्री हैं।

तुर्किये के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है भारत : मोदी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तुर्किये में आए भूकंप में लोगों की मौत पर सोमवार को शोक व्यक्त किया और कहा कि भारत इस त्रासदी से निपटने में मदद के लिए हरसंभव सहायता देने को तैयार है। दक्षिणपूर्व तुर्किये और सीरिया में सोमवार को तड़के 7.8 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे कई इमारतें ढह गईं। भूकंप संबंधी घटनाओं में कम से कम 195 लोगों की मौत की खबर है और सैकड़ों घायल हो गए हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। मोदी ने ट्वीट किया, 'तुर्किये में भूकंप के कारण हुए जान-माल के नुकसान से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।' प्रधानमंत्री ने भूकंप पर तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के एक ट्वीट को टैग करते हुए कहा, 'भारत तुर्किये के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस त्रासदी से निपटने के लिए हरसंभव सहायता देने को तैयार है।'

अदाणी मामले को लेकर विपक्ष का दोनों सदनों में जोरदार हंगामा

संसद की कार्यवाही फिर स्थगित

नई दिल्ली। बजट पेश होने के बाद से अब तक संसद में एक भी दिन चर्चा नहीं हो पाई है। गौतम अदाणी मामले को लेकर विपक्षी दल लगातार संसद के दोनों सदनों में हंगामा कर रहे हैं और इस मामले पर संसदीय कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं, उधर सत्ता पक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रहा है। सोमवार को भी हंगामे के बाद लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दिया गया है।

अदाणी मामले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों द्वारा नारेबाजी के बीच दोनों सदन 7 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए। अदाणी मामले पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) जांच चाहते हैं, सरकार हर चीज को छिपाना चाहती है। सरकार की पोल खुल गई है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हमने जो नोटिस (267) दिया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रपति के अभिभाषण से अलग विषय है। हम चाहते हैं कि पहले इस पर चर्चा हो। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन पूरे देश में जो गड़बड़ी हो रही है उस पर प्रधानमंत्री जवाब दें।

अदाणी समूह-हिंडनबर्ग मामले पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत सीपीआई (एम) सांसद एलामारम करीम ने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया। नोटिस में लिखा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदाणी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है। इसकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिन-प्रतिदिन के आधार पर निगरानी की जानी चाहिए। अदानी मुद्दे पर संसद के लिए विपक्ष की रणनीति पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अब हमारी बैठक होगी। पूरा विपक्ष एक साथ आएगा, चर्चा होगी और फैसला होगा। यह केवल कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत के आम लोगों का मुद्दा है।

अदाणी मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं चाहेंगे प्रधानमंत्री : राहुल गांधी

नई दिल्ली। हिंडनबर्ग-अदाणी विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में अदाणी मुद्दे पर चर्चा को टालने की पूरी कोशिश करेंगे। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि देश को पता होना चाहिए कि अदाणी के पीछे कौन सी शक्ति है। राहुल गांधी ने कहा, %मोदी जी संसद में अदाणी जी पर चर्चा को टालने की पूरी कोशिश करेंगे। इसका कारण आप जानते हैं। मैं चाहता हूं कि अदाणी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो लाखों-करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, वह सामने आना चाहिए।

कांग्रेस सांसद ने कहा, मैं सरकार के बारे में काफी समय से बोल रहा हूं कि हम दो, हमारे दो। सरकार डरी हुई है और संसद में अदाणी जी पर चर्चा नहीं करना चाहती है। सरकार को इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जो कब्जा किया गया है, उसकी भी जांच हो और अडाणी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वह भी देश को पता चले।

बता दें, हिंडनबर्ग रिसर्च के खुलासे के बाद कांग्रेस अदाणी मुद्दे को लेकर सरकार पर आक्रामक दिख रही है और संसद में चर्चा की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अदाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट या संयुक्त संसदीय समिति की देखरेख में निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि इस वित्तीय गड़बड़ी में अदाणी समूह में निवेश किए गए आम लोगों के करोड़ों रुपये शामिल हैं। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अदाणी समूह पर %वित्तीय गड़बड़ी और स्टॉक हेरफेरी% का आरोप लगाया गया है। यह रिपोर्ट सामने आने के बाद अदाणी समूह की कंपनियों के शेयर धराशाई हो गए हैं। इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के हंगामा के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई है।

विपक्ष ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन

अडाणी ग्रुप मामले पर विपक्ष ने सोमवार को साझा रणनीति पर चर्चा की और इसके बाद संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया। रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने अडाणी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़े मामले और कुछ अन्य विषयों को लेकर सोमवार को संसद में अपनी अपनी साझा रणनीति पर चर्चा की और परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन नेताओं ने एक बड़ा बैनर भी ले रखा था, जिस पर अडाणी स्कैन्डल या जेपीसी जांच या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो लिखा था।

खेल
प्रमुख समाचार

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी : अश्विन और नाथन के बीच होगी टक्कर

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 9 फरवरी से नागपुर में शुरू होने वाली है। इस सीरीज में चार टेस्ट मैच खेले जाएंगे। इस सीरीज के दौरान रविचंद्रन अश्विन और ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन के बीच एक खास टक्कर होगी।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैचों में अब तक सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम है। दिग्गज लेग स्पिनर कुंबले ने 20 मैचों में 111 विकेट लिए थे। भारत के रविचंद्रन अश्विन और ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन के पास बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान कुंबले को पीछे छोड़ने का मौका होगा। दोनों देशों के बीच खेले गए टेस्ट मैचों में नाथन लियोन ने अब तक 22 मैच में 94 और अश्विन ने 18 मैच में 89 विकेट लिए हैं। भारतीय पिचों को स्पिन गेंदबाजों के अनुकूल माना जाता है इसलिए चार टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान दोनों ही खिलाड़ी कुंबले से आगे निकल सकते हैं।

इसके अलावा आर अश्विन एक खास कीर्तिमान बनाने से भी सिर्फ 1 विकेट दूर हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 फरवरी से शुरू होने वाली बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट सीरीज के दौरान एक विकेट लेते ही अश्विन सबसे कम टेस्ट मैच खेलकर सबसे तेज 450 विकेट पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। 36 साल के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अब तक 88 टेस्ट मैचों में 449 विकेट लिए है।

बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट सीरीज के दौरान स्पिनरों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। भारतीय पिचों के मिजाज को देखते हुए अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल की गेंदबाजी सीरीज का नतीजा तय कर सकती है। बता दें कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज में कुल चार मैच खेले जाएंगे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 335 अंक फिसला निफ्टी में 89 अंकों की गिरावट

नई दिल्ली। कमजोर वैश्विक संकेतों के बाद लाल निशान पर खुला भारतीय बाजार बंद भी लाल निशान पर ही हुआ। सोमवार को बाजार में बिकवाल दिखी। इस दौरान सेंसेक्स 334.98 अंक टूटकर 60,506.90 अंकों पर बंद हुआ। दूसरी ओर 50 शेयरों वाला निफ्टी इंडेक्स 89.45 अंक फिसलकर 17,764.60 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 125.05 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और यह 41370.15 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, पावरग्रिड, आईटीसी और बजाज फिनसर्व के शेयर हरे निशान पर कारोबार करते हुए बंद हुए जबकि एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स और एलएंडटी के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुए।

रिजर्व बैंक के एमपीसी की तीन दिवसीय बैठक शुरू

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक आज यानी सोमवार से शुरू हो रही है। ये बैठक 3 दिन चलेगी और बुधवार को मॉनिटरी पॉलिसी सामने आएगी। बुधवार को पता चलेगा कि आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) महंगाई को काबू करने के लिए रेपो रेट में कितने बेसिस प्वाइंट का इजाफा कर सकता है। जानकारों के मुताबिक इस बार आरबीआई इस बार रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। बता दें कि हालिया आंकड़ों में रिटेल महंगाई में गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर में हुई मॉनिटरी पॉलिसी बैठक में सेंट्रल बैंक ने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट 35 बेसिस प्वाइंट बढ़ाया था। इससे पहले लगातार तीन बार में रेपो रेट में 50-50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की गई थी।

अडानी भरोसा जीतने के लिए लौटा सकते हैं 8000 करोड़ का कर्ज

नई दिल्ली। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अडानी समूह को तगड़ा झटका लगा है। कंपनी के मार्केट कैप में सौ अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हो चुका है। कंपनी को हुए नुकसान के बाद अब अडानी डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। मुश्किलों को कम करने और निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए गौतम अडानी बड़ा कदम उठाने की तैयारी में हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप एडवांस में 8000 करोड़ रुपए का कर्ज लौटाने का प्लान कर रहा है। माना जा रहा है कि कंपनी 30 से 45 दिनों के भीतर ये पैसा लौटाने रखी तैयारी कर रही है। कंपनी ने ग्लोबल बैंकों जैसे क्रेडिट सुईस, जेपी मोर्गन, जेएम फाइनेंस समेत कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियों से लोनलिया है। अडानी इन कंपनियों के लोन को लौटाने की पेशकश कर रहे है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह के इस कदम से निवेशकों की चिंताएं कम होंगी और उनपर निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

पतंजलि फूड्स के निवेशकों के डूबे 7000 करोड़

नई दिल्ली। अडानी ग्रुप और हिंडेनबर्ग के इस हल्ले के बीच योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि फूड्स कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे है। 24 जनवरी से ही पतंजलि फूड्स के शेयरों में गिरावट जारी है। 24 फरवरी को पतंजलि फूड्स के शेयर के दाम 1208 रुपये पर था, जो 3 फरवरी को गिरकर 907 रुपये पर पहुंच गया। हालांकि सोमवार को कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार खुलने के साथ शेयर मामले में तेजी देखने को मिला है। आज पतंजलि के शेयर 936.90 पर पहुंच गए है। एक हफ्ते में पतंजलि के मार्केट कैपिटल में 7000 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। पतंजलि का शुद्ध लाभ दिसंबर तिमाही में 15 फीसदी बढ़ा। इसका शुद्ध लाभ 269.18 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी के बाद भी कंपनी के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 5 महीने में निवेशकों को 18000 करोड़ से अधिक का झटका लग चुका है।

बजट से आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा

शिशिर बैजल

वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट का फोकस वृद्धि पर है तथा इसमें सामाजिक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दीर्घकालिक दृष्टि है। बजट इससे आगाह है कि अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न हिस्सों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर विकासों के लिए आवंटन बहुत अहम है।

इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के मद में 33 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी करते हुए आवंटन को 10 लाख करोड़ रुपये किया गया है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिये सस्ते आवास सुलभ कराने के मद में 66 फीसदी की वृद्धि की गयी है। इन आवंटनों से इंगित होता है कि बजट ग्रोथ एजेंडा की दिशा में अपना कदम मजबूती से आगे बढ़ाया है। ऐसा करते हुए वित्तीय मजबूती के लिए भी रोडमैप मुहैया कराया गया है, जिससे वित्तीय बाजारों को भी खुशी होगी।

सस्ते आवास पर बड़ी पहल: प्रधानमंत्री आवास योजना में आवंटन में वृद्धि महत्वपूर्ण है, जिससे देश में सस्ते आवास सुलभ कराने की प्रक्रिया की गति बनाये रखने में मदद मिलेगी। इस मद में 66 फीसदी से अधिक की वृद्धि कर आवंटन को 79 हजार करोड़ रुपये किया गया है, जिससे सभी को आवास देने की योजना में बड़ी सहायता मिलेगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा प्रोत्साहन: देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को सरकार बरकरार रखा है। केंद्रीय बजट में इस संबंध में आवंटन का महत्व यह है कि इसमें रेलवे के लिए रिकॉर्ड आवंटन, आवागमन आधारित विकास, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जलमार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डे आदि समेत सभी क्षेत्रों को सम्मिलित किया है।

शुल्कों पर अनुदान देने की घोषणा की है।

पर्यटन एवं सत्कार: बजट में पर्यटन एवं सत्कार क्षेत्र के लिए विकास का समुचित वातावरण बनाने की दिशा में उदारतापूर्ण पहलें घोषित की गयी हैं। यह दिलचस्प है कि अधिक केंद्रों को स्थापित करने की बजट घोषणा की भावना समावेशी है।

हरित विकास

स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और वनों को फिर से लगाने से जुड़े मसले, विशेषकर तटीय इलाकों में, आदि के साथ बजट में हरित विकास पर दिये गये जोर को उल्लेखनीय ढंग से रेखांकित किया जाना चाहिए। सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित वस्तुओं के आयात

लोगों के लिए अधिक नकदी

सरकार ने निम्न और मध्य आय के स्तर पर खर्च करने योग्य आमदनी को बढ़ाया है, जो उपभोग में किसी-न-किसी तरह खर्च होगा, जिससे आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा।

रियल इस्टेट सेक्टर पर असर

प्रधानमंत्री आवास योजना में 66 फीसदी की बढ़ोतरी से सस्ते आवास के विकास पर सीधा असर पड़ेगा तथा देश में आवास उपलब्धता की खाई को पाटने में मदद मिलेगी। आयकर स्लैब सीमा को बढ़ाने से लोगों के पास खर्च करने वाली आमदनी बढ़ेगी, जिसे आवास परिसंपत्ति खरीद के लिए उपयोग किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने से भी परोक्ष रूप से रियल इस्टेट सेक्टर को फायदा मिलेगा। इसे आवागमन-आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिये गये जोर के साथ जोड़कर देखें, तो विकास को और गति मिलेगी, जिससे मध्य और दीर्घ अवधि में रियल इस्टेट सेक्टर को भी लाभ होगा। कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट में की गयी घोषणाएं उपभोग बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए सकारात्मक है तथा वैश्विक महत्व की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में पहलकदमी है।

रामचरितमानस के बहाने जातिगत जनगणना

आशीष तिवारी

लोकसभा चुनावों में अभी एक साल का वक्त है, लेकिन सियासत की पिच उत्तर प्रदेश में मजबूती से तैयार होने लगी है। पिच की मजबूती के लिए रामचरितमानस के बहाने जातिगत जनगणना की गोलबंदी शुरू हो गई है। बिहार में तो जातिगत जनगणना के आंकड़े भी कुछ दिनों में आने वाले हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में इसी आधार पर सियासत का पारा जबरदस्त तरीके से गर्म हो रहा है। सियासी जानकार भी मानते हैं कि पिछड़ों की राजनीति करने और खेल बिगाड़ने का मौका विपक्ष को न मिले, इसीलिए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी सियासी दांव चलते हुए जातिगत जनगणना का समर्थन कर दिया। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की चौपाई पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के साथ पवित्र ग्रंथ को फाड़ने की घटना से सियासत उफान पर है। उत्तर प्रदेश की सियासत को करीब से समझने वाले वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति का कितना महत्व है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर राजनीतिक दल बगैर पिछड़ों की बात किए हुए उत्तर प्रदेश में सियासी कदम नहीं बढ़ा सकता। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषण राजकुमार सिंह कहते हैं कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाई पर विवादित बयान दिया, तो समाजवादी पार्टी की सियासत के नजरिए से यह बयान बहुत उर्वरा लगा। वह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रामचरितमानस की चौपाई से शुरू हुई सियासत जातिगत जनगणना पर पहुंच गई वह भी सियासत के लिहाज से बहुत उपजाऊ मानी जा रही है।

सियासी जानकारों का मानना है कि इस पूरे मामले में अगर राजनीतिक दलों को देखें तो भाजपा के लिए अब बहुत सधी हुई सियासी बयानबाजी और कवायद बेहद जरूरी मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह कहते हैं कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जातिगत जनगणना की बात कही उसमें केशव प्रसाद मौर्य के इस पूरे बयान को इसी मामले से जोड़ कर ही देखा जा रहा है। सियासी जानकार बताते हैं कि दरअसल समाजवादी पार्टी ने एक तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के चरित मानस की चौपाई पर दिए गए विवादित बयान को मूक सहमति दी है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्या के बयान से समाजवादी पार्टी पिछड़ों के लिहाज से सियासी पिच पर बैटिंग करना आसान बना जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने इसके लिए पूरी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश के सभी जिलों शहरों और गांव में एक बड़े आंदोलन की भूमिका भी बना ली। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी माहौल बनाकर आगे बढ़ रही है, उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने भी रामचरितमानस की उसी चौपाई पर दलित कार्ड भी खेल दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की राजनीति रामचरितमानस और जातिगत जनगणना की शुरू हुई है, उसके बीच में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या का जातिगत जनगणना के समर्थन के इस बयान को सपा और बसपा की रामचरितमानस की एक चौपाई पर खड़े किए गए विवाद और उसके बाद पिछड़ों की जाने वाली गोलबंदी की काट के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में पिछड़े और अति पिछड़े न सिर्फ महत्वपूर्ण हैं, बल्कि बीते चुनावों में जिस तरीके के परिणाम आए हैं, उसमें उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। हालांकि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या के बयान पर पार्टी की सहमति और असहमति तो अभी नहीं आई है।

कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष भाजपा को हरा सकता है

रमेश सर्राफ धमोरा

कभी देश पर एकछत्र राज करने वाली कांग्रेस पार्टी मौजूदा दौर में बहुत कमजोर स्थिति से गुजर रही है। 2014 के बाद तो लोकसभा में कांग्रेस को विपक्ष के नेता के का पद भी नहीं मिल पाया है। देश के अधिकांश राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी है। लगातार चुनाव हारने के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छवि भी बहुत कमजोर हो गई थी। उन्हें जनाधार विहीन नेता के तौर पर माना जाने लगा था। राजनीतिक पर्यवेक्षक भी मानने लगे थे कि राहुल गांधी में चुनाव जिताने की क्षमता नहीं है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस शायद ही फिर से देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी बन सके। इन्हीं सब आशंकाओं के मध्य राहुल गांधी ने कुछ ऐसे फैसले किए जिनसे उनकी छवि एक दृढ़ निश्चयी मजबूत नेता के रूप में उभरी है।

2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय सभी ने उनसे इस्तीफा वापस लेने के लिए बहुत दबाव भी डाला था। मगर वह अपने फैसले पर अटल रहे। अंततः सोनिया गांधी को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बनना पड़ा था। करीब तीन साल बाद कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव करवाए गए। इस दौरान भी कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने राहुल गांधी से कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने की अपील की थी। जिसे उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने पदयात्रा करने की घोषणा कर दी थी, जिसे राहुल गांधी ने पूरी कर दिखाया है। कन्याकुमारी से अपने भारत जोड़ो पदयात्रा की शुरुआत करने वाले राहुल गांधी ने बिना थके, बिना रुके लगातार चलकर 4000 किलोमीटर की अपनी पदयात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर देश की जनता को यह संदेश दिया है कि उनमें नेतृत्व करने की क्षमता आज भी बरकरार है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मजबूत होकर उभरेगी।

राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा के दौरान सभी विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित कर विपक्ष को एकजुट करने का भी सार्थक प्रयास किया था। बहुत से विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा में शामिल भी हुए। जिससे देश की जनता को एक संदेश गया कि कांग्रेस के बिना विपक्ष की राजनीति हमेशा ही अधूरी रहेगी। जब तक कांग्रेस केंद्र में नहीं रहेगी तब तक विपक्षी एकजुटता नहीं हो पाएगी। कांग्रेस के बिना भाजपा को हराना संभव नहीं है। पूरे देश में आज भी कांग्रेस का जनाधार बरकरार है। हाल ही में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में सत्तारुढ़ भाजपा को करारी शिकस्त देकर अपनी सरकार बनाई है। जिससे साबित होता है कि कांग्रेस में आज भी भाजपा से दो-दो हाथ करने का दमखम बाकी है।

राहुल गांधी द्वारा अपनी पदयात्रा में विपक्षी नेताओं को आमंत्रित करना इस बात का द्योतक है कि राहुल गांधी बड़े मन से राजनीति करना चाहते हैं। उनका इरादा सभी विपक्षी दलों को साथ लेने का है। राहुल गांधी की पदयात्रा में डीएमके, वामपंथी दल, राष्ट्रीय जनता दल, महाराष्ट्र की उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जैसी बहुत-सी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने शामिल होकर विपक्षी एकता मजबूत करने की बात कही है। इस पदयात्रा में शामिल होने वाले विपक्षी दलों के सभी नेताओं ने राहुल गांधी की सराहना करते हुए उनके साथ मिलकर विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। इससे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस एक मजबूत गठबंधन बनाकर भाजपा को सत्ता से हटाने का प्रयास करेगी।

राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए उन सभी सवालों को खारिज कर दिया है जो उन पर उठते रहे थे। पहले कहा जाता था कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा। फिर कहा गया कि वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे लेकिन वो नहीं बने। इसके बाद कहा गया कि अध्यक्ष के चुनाव को टाल दिया जाएगा लेकिन वो भी नहीं टाला गया। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने एक मजबूत और गंभीर नेता की छवि बनाई है।

इस यात्रा के जरिये राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ताकतवर विकल्प के रूप में खड़े होने की कोशिश की है। अब लोग राहुल गांधी को गंभीरता से ले रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं में भी आगे निकल गए हैं। अब तक ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, मायावती, अखिलेश यादव सभी राहुल गांधी की गंभीरता पर सवाल उठाते रहे थे। आज उन सभी को लगने लगा है कि उनके बिना विपक्ष की एकता मुमकिन नहीं है।

हर यात्रा का कोई राजनीतिक उद्देश्य होता है। राहुल की यात्रा भी इससे अछूती नहीं है। खासतौर से यह देखते हुए कि अगले साल लोकसभा चुनाव हैं। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने देश में हलचल पैदा की है। जिन-जिन राज्यों से यह पद यात्रा गुजरी है वहां पार्टी और कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। एक तरह से कहा जा सकता है इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को नई जान मिली है।

भारत जोड़ो के नारे में राहुल गांधी कितने कामयाब हुए हैं इसका पता तो बाद में चलेगा। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी जिस तरह लगातार प्रधानमंत्री को घेरते रहे उससे उन्हें फायदा हुआ है। सबसे पहले तो वो कांग्रेस के निर्विवादित नेता बन गए हैं। कांग्रेस में सभी ने राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है।

राहुल गांधी की पद यात्रा के नतीजे इसी साल से दिखने शुरू हो जाएगें। इस वर्ष राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम सहित नौ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने सरकार बचाने की चुनौती होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को स्थिति मजबूत करने की जरूरत है। यह तभी होगा जब कांग्रेस नौ राज्यों के विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करे। इन नौ राज्यों के नतीजों से ही राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी का भविष्य तय होगा।

प्रसंग — प्रमाण का असर

भारत से लौटते समय दिग्विजयी सिकन्दर के साथ थी अनिन्द्य सुन्दरी फिलिप्स । सिकन्दर उसके रूपजाल में फँसकर सब कुछ भूल गया था। फिलिप्स के इस रूपजाल को पहचाना यूनान के महान् दार्शनिक अरस्तू ने। फिलिप्स विषकन्या थी, इसलिए अरस्तू ने सिकंदर को सावधान किया, किंतु बात कुछ ही समय के लिए टल सकी। बात फिलिप्स को पता चली और वह अरस्तू से चिढ़ गयी। बदला लेने के लिए उसने अरस्तू पर भी रूपजाल फेंक दिया और वे उसके पीछे ऐसे पागल हुए कि निम्नतर कार्य करने को तैयार हो गये। एक दिन फिलिप्स ने अरस्तू को घुटनों के बल घोड़ा बनाया, लगाम डाली और उनकी पीठ पर जीन कसकर सवार हो गयी। उसने उनकी पीठ पर चाबुक मारकर उन्हें सारे कमरे में दौड़ाया। अकस्मात् सिकंदर वहाँ पहुँचा और उसने जब यूनान के महान् विद्वान् की वह दीन-हीन दशा देखी, तो वह आश्चर्य से हतबुद्धि रह गया। उसने अरस्तू से प्रश्न किया, यह सब क्या है ? दार्शनिक ने धीर-गम्भीर स्वर में उत्तर दिया, जो रमणी मुझ जैसे व्यक्ति से यह सब करवा सकती है, वह मुझसे कम आयुवाले अनुभवशून्य युवक के लिए क्या अधिक खतरनाक नहीं हो सकती ? मैंने तुम्हें पहले सावधान किया था और उसका असर न होते देख अब प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है!

आज की महत्वपूर्ण घटनाएं

1997 यूएस और रूस ने हेलसिंकी के लिए 20 से 21 मार्च को शिखर सम्मेलन की घोषणा की।
1998 नागानो जापान में 18 वें शीतकालीन ओलंपिक खेल खोले गए।
1999 अब्दुल्ला द्वितीय अपने पिता राजा हुसैन की मृत्यु के बाद जॉर्डन के हाशमाइट राज्य का राजा बन गया।
2001 इस्रायल के प्रधानमंत्री एहुद बराक चुनाव में पराजित, एरियल शेरोन नए प्रधानमंत्री बने।
2006 लाल सलाम में 1200 से अधिक लोगों की हत्या करने के बाद मिस्र के एक नौका को सलाम बोकासिआको डूब गया।
2008 स्पेस शटल अटलांटिस ने आईएसएस को प्रयोगशाला पहुंचाने के लिए एसटीएस 122 का शुभारंभ किया।
2009 ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में सबसे घातक ब्रशफ़ाइक के बाद, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में उच्चतम तापमान दर्ज करता है।
2010 महमूद अहमदीनेजाद, ईरानी राष्ट्रपति ने ईरान की परमाणु एजेंसी को उच्च स्तर पर यूरेनियम को समृद्ध करने की आज्ञा दी।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

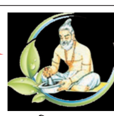

पैङ्गलोपनिषद् (भाग-6)

गतांक से आगे...

अकस्मात् मुद्गर और दण्ड आदि के द्वारा ताड़ित किये जाने पर जिस प्रकार व्यक्ति कम्पित होता है, उसी प्रकार मूर्च्छा की स्थिति में भी भय और अज्ञान के कारण समस्त इन्द्रियाँ कम्पित होती हैं। यह अवस्था (मूर्च्छा) मृत तुल्य होती है। जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और मूर्च्छा अवस्थाओं से भिन्न एक अवस्था है, जो ब्रह्म (अत्यधिक महान) से लेकर तिनका (अत्यधिक तुच्छ) पर्यन्त सभी जीवों के लिए भयप्रदा है, जिसके प्राप्त होने पर स्थूल शरीर का परित्याग करना पड़ता है, वह मरणावस्था होती है।

उस समय (मृत्यु हो जाने पर) कर्मेन्द्रियों, ज्ञानेन्द्रियों, उनके विषय (तन्मात्राओं), प्राणों को एकत्र करके काम और कर्म से समन्वित हुआ जीव अविद्या से आवेष्टित होकर अन्य शरीर को प्राप्त करके दूसरे लोक (परलोक) में गमन करता है। पूर्वकृत कर्मों के फलभोग में फँसे रहने के कारण वह (जीव), उसी प्रकार शान्ति प्राप्त नहीं कर पाता, जिस प्रकार भँवर में फँसा हुआ कीट सत्कर्मों के परिपक्व हो जाने पर जब अनेक जन्मों के पश्चात् मनुष्य की मोक्ष प्राप्त करने को (बलवती) इच्छा उत्पन्न होती है, तब वह किसी सद्गुरु का अवलम्बन लेकर, लम्बे समय तक उनकी सेवा करके (ज्ञान प्राप्ति के पश्चात्) बन्धन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

अविचार करने से बन्धन और विचार (सद्विचार) करने से मोक्ष होता है। इसलिए सदैव विचार (सद्विचार) करना चहिए। अध्यारोप और अपवाद से स्वरूप का निश्चय किया जा सकता है। इसलिए सदा जगत, जीव और परमात्मा के विषय में ही विचार (चिन्तन) करना चाहिए। जीव भाव और जगद्भाव का निराकरण करने से अपने प्रत्यगात्मा (जीव) से अभिन्न केवल ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है।

पारमार्थिक जीव के ऊपर अव्यक्त का अंश रूप अज्ञान आच्छादित है। वह भी ब्रह्म का ही अंश है। तत्त्वमसि आदि वाक्यों से ब्रह्म की एकता प्रकट होती है, परन्तु व्यावहारिक और प्रातिभासिक अंश ब्रह्म से इस प्रकार की एकता नहीं रखते। अन्तःकरण में जो चैतन्य प्रतिबिम्बित होता है, वही अवस्थात्रय (जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति) का भागी होता है। चैतन्य तत्त्व ही उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होकर घटीयन्त्र के समान उद्विग्न (चंचल) होता है, जो निरन्तर जन्म-मरण को प्राप्त होता रहता हैं ।

क्रमशः

कवि प्रदीप के लिखे देशभक्ति गीत को सुनकर रो पड़े थे नेहरू

देश में यूं तो कई कवि और गीतकार हुए हैं लेकिन कवि प्रदीप उन महान शख्सियों में शामिल हैं जिनके लिखे गीतों ने देशवासियों में नया जोश और जज्बा भर दिया था। उनके लिखे देशभक्ति गीत आज भी हर किसी में राष्ट्रप्रेम की भावना भर देते हैं। उनके एक गीत को सुनकर तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहलाल नेहरू की आंखें भी भर आई थीं।

भारतीय कवि और प्रसिद्ध गीतकार कवि प्रदीप की सोमवार को जयंती थी। उनका जन्म 6 फरवरी 1915 को हुआ था। कवि प्रदीप का पूरा नाम रामचरण द्विवेदी था। उन्हें उनके देशभक्ति गीत 'ऐ मेरे वतन के लोगों' के लिए खास तौर पर जाना जाता है। ये गीत उन्होंने चीन-भारत युद्ध के दौरान शहीद हुए देश के सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए लिखा था। बता दें कि उज्जैन के पास छोटे से मध्य भारतीय कस्बे बड़नगर के एक मध्यमवर्गीय औदिच्य ब्राह्मण परिवार में जन्में कवि प्रदीप ने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की थी। उन्हें बचपन से ही हिंदी कविता लिखने का शौक था। उनके लिखे देशभक्ति गीत 'ऐ मेरे वतन के लोगों' से वह घर-घर मशहूर हो गए थे। दरअसल चीन से युद्ध हारने के बाद देश के नौजवानों में निराशा भर गई थी जिसके बाद कवि प्रदीप ने अपनी कलम को बंदूक बना लिया और उन्होंने ऐतिहासिक गीत 'ऐ मेरे वतन के लोगों' की रचना कर डाली। उनके इस गीत से जुड़ा एक वाकया भी है। 26 जनवरी 1963 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने दिल्ली के रामलीला मैदान में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में जब 'ऐ मेरे वतन के लोगों' का गायन किया था तो इस गीत को सुनकर नेहरू जी की आंखें भर आई थी। बाद में नेहरू जी ने कवि प्रदीप को इस गीत के लिए बधाई दी थी। पंडित नेहरू ही नहीं इस गीत को सुनकर लोगों में भी देशभक्ति की लहर दौड़ गई थी। युवाओं में जोश भर गया था। कहना गलत नहीं होगा आज भी ये गीत हर किसी के रोम-रोम में बसा है।

कवि प्रदीप ने कई फिल्मों के लिए देशभक्ति गीत लिखे थे। उन्हें पहचान 1940 में आई फिल्म बंधन के लिए लिखे देखभक्ति गीतों से मिली। इस फिल्म के गीतों ने हर किसी में देशभक्ति का जज्बा भर दिया था। फिल्म के रिलीज होने के बाद कवि प्रदीप को तुरंत अंडरग्राउंड होना पड़ा था ताकि ब्रिटिश हुकूमत उन्हें गिरफ्तार न कर सके। कवि प्रदीप की बेटी मितुल प्रदीप ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि, 1943 में आई फिल्म 'किस्मत' में उनके पिता के लिखे गीत 'दूर हटो ऐ दुनियावालों।।' की वजह से भी ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इस वजह से उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा था। कवि प्रदीप ने अपने करियर में लगभग 1700 गाने लिखे। उन्होंने फिल्मी गीतों सहित राष्ट्रवादी कविताएं भी लिखी। 1940 में आई फिल्म चलन में चल चल रे नौजवान जैसा हिट गाना भी कवि प्रदीप ने लिखा था। कवि प्रदीप लिखते तो थे ही वहीं वे गाते भी थे। उन्होंने फिल्म 'जागृति' के 'आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की गाया भी था।

अमेरिका में चीन का जासूसी गुब्बारा

गौतम मोरारका

चीन दुनिया का सबसे ताकतवर देश भले नहीं है लेकिन जासूसी के मामले में वह दुनिया में सबसे बड़ा चैम्पियन है। अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देशों में अपने अवैध चीनी पुलिस स्टेशनों का संचालन हो, अमेरिका में लगातार घुसपैठ करने के प्रयास हों या फिर मोनटाना इलाके में विशालकाय गुब्बारे के माध्यम से अमेरिका की जासूसी कराने की बात हो...ड्रैगन हर वह कदम आजमा रहा है जोकि उसे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका के बारे में गुप्त जानकारियां मुहैया करा सकता है। चीन को लेकर अमेरिका की चिंता स्वाभाविक भी है क्योंकि हाल के दिनों में अमेरिका में कई स्थानीय लोगों के पास से चीनी हथियार बरामद हुए, अमेरिकी सेना में चीनी जासूस पकड़ा गया इसके अलावा हालिया कई साइबर हमलों में चीन का हाथ सामने आया जिससे बाइडन प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है।

जहां तक अमेरिका में आये चीनी गुब्बारे की बात है तो आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने बताया है कि अमेरिका के हवाई क्षेत्र में चीनी जासूसी गुब्बारा देखा गया है जिसका आकार "तीन बसों" के बराबर बताया जा रहा है। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर के मुताबिक, अमेरिकी सरकार को एक जासूसी गुब्बारे का पता चला है और उस पर नज़र रखी जा रही है। पैट राइडर ने कहा, "गुब्बारे के बारे में पता चलते ही अमेरिकी सरकार ने संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत कार्रवाई की।" उन्होंने कहा कि गुब्बारा वाणिज्यिक हवाई क्षेत्र से काफी ऊंचाई पर है और इससे जमीन पर लोगों को कोई खतरा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को इस घटना के बारे में जानकारी दी गई है और पेंटागन इससे निपटने के लिए तमाम विकल्पों पर गौर कर रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की चीन यात्रा से कुछ दिन पहले यह घटना घटी है।

वैसे जिस क्षेत्र में चीनी जासूसी गुब्बारा उड़ता दिखाई दिया वहां सैन्य लिहाज से अमेरिका के महत्वपूर्ण ठिकाने हैं। अमेरिका में सवाल यह भी उठ रहा है कि यह गुब्बारा आखिर वहां तक पहुँचा कैसे और क्यों पहले इस पर नजर नहीं पड़ी? अमेरिका में विपक्ष ने यह भी सवाल किया है कि क्यों चीनी गुब्बारे को गिराने के लिए तत्काल आदेश नहीं जारी किये गये? इस संबंध में हालांकि अमेरिकी सरकार का कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है लेकिन बताया जा रहा है कि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिली और अमेरिकी उत्तरी कमान के जनरल ग्लेन वैनहर्क ने जमीन पर लोगों की सुरक्षा को संभावित खतरे के मद्देनजर कार्रवाई करते समय विशेष सावधानी बरतने को कहा है। बताया जा रहा है कि चीनी गुब्बारे पर कार्रवाई करने के लिए अमेरिका के एफ-22 लड़ाकू विमानों को तैयार रखा गया है। हालांकि अमेरिकी सरकार की पहली प्राथमिकता यही दिखी कि संवेदनशील सूचनाओं को विदेशियों के हाथ लगने से रोका जाये। अमेरिकी अधिकारियों का यह भी कहना है कि जासूसी गुब्बारा नागरिक उड्डयन के लिए कोई खतरा नहीं था क्योंकि वह वाणिज्यिक एयरलाइनों द्वारा उपयोग की जाने वाली हवाई ऊंचाई से काफी ऊपर था। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि चीन अपने उपग्रहों का उपयोग करके पहले ही जो जानकारी एकत्र कर सकता है, उससे अधिक जानकारी यह जासूसी गुब्बारा हासिल नहीं कर पायेगा।

उधर, मोनटाना क्षेत्र जहां चीनी जासूसी गुब्बारा दिखा है वह कम आबादी वाला क्षेत्र भले है लेकिन अमेरिका के लिए यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर अमेरिकी एयरफोर्स का स्पेशल बेस है, साथ ही यहां पर अमेरिका के कुछ परमाणु ठिकाने भी बताये जा रहे हैं। खबरें हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द ही रूस का दौरा करने जा रहे हैं इसलिए यह चीन का एक प्रयास भी हो सकता है कि अमेरिका की परमाणु ताकत का अंदाजा लगाया जाये और उस पर जिनपिंग अपने रूस दौरे के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से चर्चा कर सकें।

बात अमेरिका में चीनी पुलिस स्टेशनों की करें तो आप भी इसके बारे में सुनकर चौंक जाएंगे क्योंकि अमेरिका में सुरक्षा के कितने सख्त प्रबंध होते हैं यह किसी से छिपा नहीं है खासकर 9/11 के बाद से अमेरिका में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये जाते हैं लेकिन ऐसे सभी सुरक्षा इंतजामों को भेदते हुए चीन अमेरिका के मैनहट्टन में अपना एक पुलिस स्टेशन चला रहा था। पिछले महीने न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि आपराधिक मामले की जांच के तहत एफबीआई ने चीनी इमारत से दस्तावेजों को जब्त किया था। यह जांच पिछले साल चाइनाटाउन की एक इमारत में हुई थी। बताया जाता है कि मैनहट्टन स्थित चीनी %पुलिस स्टेशन% के बारे में सबसे पहले एनजीओ सेफगार्ड डिफेंडर्स की एक रिपोर्ट ने खुलासा करते हुए बताया था कि अमेरिका, सर्बिया और फ्रांस समेत कई देशों में विभिन्न चीनी प्रांतों और शहरों की ओर से 100 से अधिक पुलिस स्टेशनों का संचालन किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिका में चार चीनी पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं जिनमें से दो न्यूयॉर्क, एक लॉस एंजिल्स और एक अन्य जगह पर स्थित है।

हम आपको बता दें कि चीन के इन पुलिस स्टेशनों का काम होता है कि उस देश की खुफिया जानकारी चीन तक पहुँचाएं। यही नहीं, यह चीनी पुलिस स्टेशन स्थानीय अधिकारियों का सहयोग लिये बिना विदेशों में आपराधिक मामलों को सुलझाने जैसे साहसिक काम भी करते हैं। यह चीनी पुलिस स्टेशन उस देश में रह रहे चीनी नागरिकों की छोटे-मोटे सरकारी कामों में भी मदद करते हैं। इन चीनी स्टेशनों का यह भी काम होता है कि पश्चिमी देशों में अपनी सरकार से असंतुष्ट लोगों पर नजर रखें और उन्हें जासूसी के लिए प्रेरित करें। यही नहीं, यह चीनी पुलिस स्टेशन विदेशों में चीन से भागकर आये भगोड़ों को पकड़ कर उन्हें स्वदेश वापसी पर मजबूर भी करते हैं।

गांधी आज

सविनय अवज्ञा (भाग-2)

सरकार प्रतिबंध की आज्ञा के लिए जो दलीलें देती है वे उसे वाजिब मालूम होती हों, अथवा ऐसे हुक्मों को तोड़े जाने में सरकार और जनता के झगड़े के मूल विषय किनारे रह जाते हों और दूसरे अप्रस्तुत विषय महत्त्व प्राप्त कर लेते हो, और जनता का ध्यान असली विषय की तरफ से हटकर इन छोटी-छोटी बातों पर लग जाने की संभावना हो। ऐसे कारण न होने पर ऐसी आज्ञा का सविनय अवज्ञा रूप सत्याग्रह किया जा सकता है।

इसी तरह सत्याग्रही सरकार को इसलिए कर देता है, कि उस राज्य को कायम रखना वह इष्ट समझता । पर यदि उसे यह निश्चय हो जाय कि इस राज्यव्यवस्था का नाश करना ही धर्म है तो उस राज्य को कर देने के कानूनों को वह तोड़ सकता है; परंतु इसीके साथ उस राज्य से किसी तरह का फायदा वह कोशिश करके न उठाएगा।

जहाँ प्रजासत्तात्मक शासन-पद्धति हो, या सरकार और जनता में सामान्यतः सहयोग हो, अथवा तीव्र आंदोलन का अभाव हो, वहाँ भी व्यक्तिगत अधिकारियों द्वारा गलतफहमी से अथवा हुकूमत के नशे में, अन्यायकारी आज्ञाएं निकाली जाने की संभावना रहती है। ऐसी फुटकर अन्यायी आज्ञाओं को सदा सविनय अवज्ञा का विषय बनाना उचित नहीं। यह नहीं मान लेना चाहिए कि ऐसे अन्यायों को सह लेने से हानि होती है। उस समय जनता तथा नेताओं द्वारा दिखाया हुआ धीरज और उदारता जनता को अच्छी शिक्षा देनेवाली साबित होती है। जो इस प्रकार, भय से नहीं बल्कि जानबूझकर, अन्यायों को सह लेना और आज्ञा का पालन करना जानते हैं वही मौका पड़ने पर, सविनय अवज्ञा भी उत्तम रीति से कर सकते हैं।

यदि सविनय अवज्ञा का आंदोलन ऐसा रूप ग्रहण कर ले जिससे विरोधी अथवा तटस्थ लोगों के जान-माल को हानि पहुँचती हो, या बेकसूर सताए जाते हों और सत्याग्रही यह अनुभव करे कि वह इसे रोकने में समर्थ है तो वह आंदोलन को स्थगित कर देगा और अपनी सारी ताकत उस हानि और उत्पीड़न को रोकने में लगा देगा।

संक्षिप्त समाचार

निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं पेंशन के लिए शिविर 9 फरवरी से

बिलासपुर। दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरित करने के पूर्व जांच-नांप शिविर और पेंशन निराकरण के लिए जिले के चारों विकासखण्डों में 9 फरवरी से शिविर लगाया जाएगा। विकासखण्ड कोटा के करगीकला में 9 फरवरी, चपोरा में 16 फरवरी एवं जनपद पंचायत कोटा में 24 फरवरी को शिविर लगाया जाएगा। इसी प्रकार तखतपुर विकासखण्ड के सफरीभांठा में 10 फरवरी, गिरधौना में 15 फरवरी एवं जनपद पंचायत तखतपुर में 22 फरवरी, मस्तूरी विकासखण्ड के सीपत में 13 फरवरी, पचपेड़ी में 20 फरवरी एवं जनपद पंचायत मस्तूरी में 23 फरवरी, बिल्हा विकासखण्ड के दगौरी में 14 फरवरी, सेंवार में 17 फरवरी, टेकर में 21 फरवरी एवं मदनपुर सिंघरी में 28 फरवरी को शिविर लगाया जाएगा। शिविर का समय सवेरे 11 बजे से शाम 4 बजे तक है। यह शिविर समाज कल्याण विभाग एवं जिला पुनर्वास केंद्र के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। जिला पुनर्वास अधिकारी ने अपील की है कि दिव्यांगजन शिविर में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र या गरीबी रेखा कार्ड, पासपोर्ट फोटो, यूनिक आई डी या विशिष्ट पहचान पत्र की छायाप्रति एवं ग्राम पंचायतों में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं में शिकायत या नवीन आवेदनों के समाधान हेतु आधार कार्ड, बैंक खाता, पासबुक आदि दस्तावेज के साथ उपस्थित होना होगा।

टीबी मरीजों की सहायता करेंगे निक्षय मित्र

बिलासपुर। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान नि-क्षय 2.0 चलाया जा रहा है, जिससे वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन किया जा सके। अभियान अंतर्गत टीबी मरीजों का इलाज पूर्ण होने तक अतिरिक्त पोषण आहार, जांच की सुविधा एवं रोजगार मूलक सहायता दिये जाने हेतु नि-क्षय मित्र बनाया जाएगा। टीबी मरीजों को उपचार के दौरान अतिरिक्त सहायता प्रदान करने वाले दानदाताओं को निक्षय मित्र के रूप में अनुबंधित कर निक्षय पोर्टल में पंजीयन किया जाएगा। इसके लिए जिले में संचालित समस्त विभागों में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, गैर सरकारी संगठनों, औद्योगिक संस्थानों आदि को निक्षय मित्र बनाने हेतु प्रेरित किया जाएगा ताकि अभियान का सफलतापूर्वक संचालन कर जिले को टीबी मुक्त किया जा सके। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला क्षय अधिकारी एवं जिला समन्वयक के दूरभाष नं. 98279-02838 पर संपर्क किया जा सकता है।

पद्मा ने इंटरनेशनल कराटे में जीता गोल्ड

रायपुर। छत्तीसगढ़ की कराटे प्लेयर पद्मा ब्यौहार ने एक बार फिर विशाखापट्टनम अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त कर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। साथ ही जूनियर 14 साल से कम उम्र की प्रतियोगिता में रायपुर की ही श्रीजल एवं साक्षी श्रीवास्तव ने गोल्ड एवं सिल्वर प्राप्त किया है गौरतलब है की कराते इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन और आंध्र प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन 3 फरवरी से 5 फरवरी किया गया है। पद्मा के कोच रमेश प्रधान ने बताया की पद्मा ने 5 फरवरी को सुबह सीनियर केटेगरी के कांता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है।

23 फरवरी को आरंग तहसील कार्यालय में लगाए जायेंगे राजस्व शिविर

रायपुर। रायपुर जिला के राजस्व प्रकरणों- नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन, किसान किताब, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र , निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु तहसील कार्यालयों में राजस्व शिविर लगाया जा रहा है। इसी तारतम्य में 16 फरवरी को धरसीवां और 23 फरवरी को आरंग में शिविर आयोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि रायपुर तहसील कार्यालय में 4 फरवरी को शिविर आयोजित किया गया था। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने शिविर में अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए है।

छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान 2 हजार 626 वाहिनी गठित

रायपुर। लोगों को व्यसन के दुष्प्रभाव से जागरूक करने और व्यसन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में 2 हजार 626 भारत माता वाहिनी का गठन किया गया है। इन वाहिनियों के माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में नशा मुक्ति के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने व्यसन मुक्ति अभियान को लेकर विशेष तौर पर निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत भारत माता वाहिनी योजना का संचालन किया जा रहा है। नशामुक्ति अभियान के तहत पूरे छत्तीसगढ़ में ग्राम स्तर से लेकर जिला एवं राज्य स्तर पर समितियों का गठन किया जा रहा है।

जनाक्रोश पदयात्रा के तीसरे दिवस पर समस्याओं के अंबार से रूबरू हुए भाजपाई

दुर्ग शहर के बीच से बहने वाले शंकर नाला के संधारण में विलंब क्यों - जितेन्द्र वर्मा

दुर्ग। भारतीय जनता पार्टी की जनाक्रोश पदयात्रा भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में तीसरे दिन चंडी शीतला मंडल अंतर्गत वार्ड क्र. 56 बघेरा से प्रारंभ की गई। चंडी शीतला मंडल के बड़े क्षेत्र में आज भी ग्रामीण परिवेश की बसाहट है। क्षेत्र के नयापारा, राजीव नगर, मठपारा, गयानगर से होकर जब गुजर रही थी तो जनता को मूलभूत सुविधाएं पानी, सड़क, साफ सफाई के साथ-साथ पट्टा वितरण को शहर प्रशासन के द्वारा जानबूझकर रोककर रखा गया है। यात्रा के शुरुआत से ही जनता का भारी जनसमर्थन मिला, लोग स्वस्फूर्त अपनी समस्या लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के पास पहुंचे, तत्पश्चात रैली शीतला नगर, गोंडपारा, गिरधारी नगर, शंकरनगर, विजय नगर, हरनाबांधा,लुचकीपारा का भ्रमण करते हुए लुचकीपारा स्थित होटल मान चौक में आमसभा कर पदयात्रा का समापन किया गया। पदयात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जनता के हित का ख्याल रखते हुए यह पदयात्रा कर रही है और चंडी शीतला मंडल के वार्डो की समस्याओं को देखकर लगता है कि जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश एवं दुर्ग नगर में बैठी है तब से यहां पर विकास थम सा गया है दुर्ग के कई इलाकों गया नगर,पोटिया, सिकोला बस्ती,आदित्य नगर,जवाहर नगर,बघेरा,सहित कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत है। दुर्ग नगर निगम के 60 वार्डो में दर्जन भर से ज्यादा ऐसे वार्ड है, जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, हर साल

गर्मी के दिनों में यह समस्या बनी रहती है। अमृत मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 152 करोड़ रुपए देने के बावजूद लोगों को पेयजल नहीं मिल रहा है। विगत कुछ दिनों से पानी विकराल समस्या है। मैं दुर्ग शहर के महापौर धीरज बाकलीवाल से पूछना चाहता हूं दुर्ग शहर के सभी 60 वार्डो की जनता आपका हिस्सा है लेकिन भाजपा पार्षदों के वार्डो से आपके द्वारा छल क्यों किया जा रहा है ? जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने खुलकर आरोप लगाया कि महापौर और विधायक अरुण वोरा की स्वेच्छाचारिता और मनमानी और प्रताड़ना से तंग आकर नगर निगम के 5 अधिकारियों ने नौकरी छोड़ दी है। कांग्रेस ने नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति का हाफ करने का वादा किया था परंतु जनता के साथ छल किया गया और विगत 4 सालों से लगातार पूरा संपत्ति कर वसूला जा रहा है, इस प्रकार जनता से झूठा वादा किया। कांग्रेस द्वारा नगरीय निकाय चुनाव के घोषणा पत्र में यूजर चार्ज समाप्त करने का वादा करके उसे पूरा नहीं किया।

भारतीय रेलवे यात्री सुविधाओं का कर रही है विस्तार-साव

बिलासपुर। आज जैसे ही नर्मदा एक्सप्रेस करगी रोड, बेलगहना रेलवे स्टेशन में रुकी तो क्षेत्र की जनता गाजे-बाजे के साथ नाचने लगी। नारेबाजी करते हुए भाजपाइयों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद अरुण साव को फूल माला से लाद दिया। आज करगी रोड में काफी संख्या में भाजपाई फिर से नर्मदा एक्सप्रेस के स्टॉपेज का स्वागत करने के लिए गाजे-बाजे के साथ पहुंचे थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद अरुण साव ने कहा है कि कोविड-19 के कारण रेल प्रशासन के द्वारा यात्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेशनों में यात्री ट्रेनों का ठहरावयहां बंद कर दिया गया था । अब हालात सामान्य होने के बाद फिर से भारतीय रेलवे में बिलासपुर रेलवे जोन स्टेशन के स्टेशनों में ट्रेनों का ठहराव शुरू कर दिया है । इसी कड़ी में नर्मदा एक्सप्रेस के बाद 3 साल बाद करगी रोड एवं बेलगहना रेलवे स्टेशन स्टॉपेज मिलने के बाद सभी यात्रियों तथा भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है । सांसद अरुण साव ने कहा है कि यात्रियों को सुविधा मिलेगी। जिसके लिए संकल्पित यात्री सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 8000 करोड़ की सौगात दी है। इससे यात्री सुविधा का विस्तार भी होगा तथा तथा लोगों को बेहतर सुविधा दिलाने भारतीय रेलवे 40 हजार करोड़ के विकास के काम चल रहे हैं।

ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की जाएः मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए नई उद्योग नीति की तर्ज पर जल्द ही ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। श्री बघेल आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को गोबर क्रय तथा लाभांश राशि के ऑनलाईन वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में 8 करोड़ 23 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी की।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गौठान से जुड़े रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अधिकतर जगहों पर क्रियाशील हो रहे हैं। अब यह पूर्णरूप से कार्य करें उसके पहले हमें ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की दिशा में कार्य करना होगा इसके लिए संबंधित विभाग जल्द प्रक्रिया पूर्ण करें। जिससे कि जब पूर्ण रूप से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो इनसे जुड़े हितग्राहियों को बैंक से ऋण लेना तथा अन्य व्यवसाय शुरू करने में मदद मिल सके।

मुख्यमंत्री ने पशुपालकों सहित गौठान से जुड़े महिला समूहों को बधाई देते हुए कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि वे लगातार रिकार्ड बना रहे हैं। 8.23 करोड़ के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 403 करोड़ 58 लाख रूपए हो जाएगा। इसी प्रकार गोबर विक्रेताओं को 4.76 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 206 करोड़ 49 लाख रूपए हो जाएगा। उन्होंने गोबर से बिजली उत्पादन के लिए शुरू की गई बिजली यूनिट पर खुशी जाहिर करते हुए, इन यूनिटों से उत्पादित बिजली को पॉवर ग्रिड से जोड़ने और बिजली की कीमत तय करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि यह गर्व की बात है कि राज्य में अब तक 4927 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की जमा पूंजी से गोबर क्रय करने लगे हैं।

देवपुर मेला में लोकरंजनी रायपुर के कलारों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति

रायपुर। श्री पातालेश्वर महादेव डोंगेश्वर धाम देवपुर के डोंगा पथरा मेला मैदान क्षेत्र में मांघी पूर्णिमा के अवसर पर दो दिवसीय भव्य मेला का शुभारंभ मेला समिति द्वारा किया गया। संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से 5 फरवरी 2023 को रात्रि 9 बजे से डॉ. पुरुषोत्तम चंद्राकर कृत लोकरंजनी लोक कला सांस्कृतिक समिति रायपुर की भव्य प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम अतिथि स्वागत श्री पातालेश्वर महादेव डोंगेश्वर धाम जन समिति देवपुर के अध्यक्ष दाऊ दिनेश कुमार चंद्राकर एवं सचिव कृष्ण कुमार मरकाम के कर कमलों से छत्तीसगढ़ी लोककला के संरक्षण एवं संवर्धन तथा पारंपरिक लोकगीत नृत्य एवं वेशभूषा से सुसज्जित लोकरंजनी लोककला सांस्कृतिक समिति रायपुर के संचालक डॉ. पुरुषोत्तम चंद्राकर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को देखने देवपुर क्षेत्र एवं आसपास के हजारों दर्शक उपस्थित रहे। देवपुर के इस पावन धरा का धार्मिक एवं आध्यात्मिक और सामाजिक समागम केंद्र सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति करते हुए डॉ. पुरुषोत्तम चंद्राकर ने बताया कि आगामी 10 फरवरी को दीनदयाल ऑडिटोरियम में इतिहास संकलन के आयोजन में कार्यक्रम 12 फरवरी को राजीव मेला में कार्यक्रम 19 फरवरी को बिलासा महोत्सव बिलासपुर में कार्यक्रम एवं 25 फरवरी को रायपुर के पूरेना में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे।

एसबीआई कार्यालय के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन

रायपुर। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरा देश खासकर मध्यम वर्गीय परिवार चिंतित है मोदी सरकार द्वारा अडाणी समूह में एसबीआई एवं एलआईसी जैसी सरकारी संस्थाओं के बेहद जोखिम भरे लेनदेन और निवेश ने भारत के निवेशकों एलआईसी एवं एसबीआई के खाताधारकों कर के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। जिसके विरोध मे आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व मे विरोध प्रदर्शन किया। जयस्तंभ चैक

स्थित एसबीआई कार्यालय के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार से मांग की है कि अडानी समूह से जो लेनदेन हुआ है उसकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश या संयुक्त संसदीय समिति के तहत निष्पक्ष जांच होए उन्होंने कहा कि एलआईसी एसबीआई व अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के जबरदस्त निवेश पर संसद मे चर्चा की जानी चाहिए और निवेशकों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने जाने चाहिए। विधायक सत्यनारायण शर्मा विकास उपाध्याय ने केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश का हर वर्ग चिंतित है लेकिन सरकार इस पर पर्दा डाल रही है केंद्र सरकार व्यक्ति विशेष को लाभ पहुचाने के लिए कार्य कर रही है शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि अडानी समूह की जा शेयर्स एसबीआई और एलआईसी ने खरीदे है उसकी जेपीसी के जरिए जांच हो या यह पैसे क्यो दिया गया किन शर्तो पर दिया गया इसकी जांच होनी जरूरी है। नुक्कड़ नाटक के जरिए मोदी और अडानी की दोस्ती दिखाई गई। शहर कांग्रेस कमेटी ने जय स्तंभ चैक पर नुक्कड़ नाटक भी किया जिसमे उद्योगपति गौतम अडानी एवं नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहने कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए है प्रदर्शन के माध्यम से दोनो मे गहरी दोस्ती दिखाई गई।

भगत ने किया माघी पूर्णिमा एवं आदिवासी मेले का शुभारंभ

बिलासपुर। खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने आज ऐतिहासिक नगरी रतनपुर में 7 दिवसीय माघी पूर्णिमा एवं आदिवासी विकास मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि विस्मृत होती जा रही छत्तीसगढ़ की संस्कृति एवं कलाओं को पुनर्जीवित कर पुष्पित पल्लवित करने का बीड़ा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने उठाया है। छत्तीसगढ़िया कहलाने में अब हम सबको गर्व का अनुभव होता है।

समारोह की अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष मनोहर राज ने की। मुख्य अतिथि की आसंदी से मंत्री श्री भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, तीज-तिहार एवं परम्पराओं से हमारी मूल पहचान हैं। इन परम्पराओं को आगे बढ़ाना हम सबका सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारी संस्कृति को हमें भूलना नहीं है,बल्कि इनमें उत्साह पूर्ण भागीदारी निभाकर विभिन्न माध्यमों से इसे आगे ले जाना है। राज्य सरकार हमारी संस्कृति

को जीवंत बनाने एवं गरिमा प्रदान करने में निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय कलाकारों की पहले उपेक्षा होती थी। हमारी सरकार ने उनको काफी महत्व दिया है। लगभग 12 करोड़ रूपये का काम इस साल दिया गया है। इसके पहले उन्हें साल भर में केवल 4-5 करोड़ रूपये के कार्यक्रम मिल पाते थे। खाद्य मंत्री ने कहा कि धान के कटोरे के रूप में भी हमारी पहचान को निरंतर बनाये रखने में सफल हुए हैं। देश में सर्वाधिक कीमत पर धान खरीदी का काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। किसानों के आमदनी बढ़ाने की बात देश में जहां पर भी आती है, तब छत्तीसगढ़ मॉडल पर जरूर विचार किया जाता है। अनेक राज्य छत्तीसगढ़ की मॉडल को बेहतर बताकर इसे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल धान खरीदी के बदले लगभग 22 हजार करोड़ रूपए का भुगतान किसानों के खातों में गया है, जो कि मेला-मड़ई उत्सव में खुशी के रूप में प्रदर्शित हो रही है। नगरपालिका अध्यक्ष श्री घनश्याम रात्रे एवं जनपद अध्यक्ष श्री मनोहर सिंह राज ने भी समारोह को सम्बोधित किया।

इस अवसर पर एसडीएम श्री हरिओम द्विवेदी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष सुमन जायसवाल, नगरपालिका उपाध्यक्ष कन्हैया यादव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीण, किसान उपस्थित थे।

बेटियाँ देश का भविष्य - विधायक शर्मा

रायपुर। कचहरी चौक स्थित डागा कन्या महाविद्यालय में आज विज्ञान प्रदर्शनी एवं वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्रामीण विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा थे। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय की छात्राएं बहुत होशियार है और अल्प आयु में ही इनमें सोचने और समझने की शक्ति अच्छी है।

उन्होंने कहा कि महाविद्यालय शिक्षण व्यवस्था बहुत अच्छी है, बेटियां आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटियाँ अनुशासन में रहकर कालेज का नाम रौशन करें। उन्होंने प्राचार्य से कहा कि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं की काउंसिलिंग करें और जो बेटी जिस दिशा में जाना चाहती उसे उसी दिशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। बेटियां देश का भविष्य होती हैं, मैं बेटियों के

सफल जीवन के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।

इस अवसर पर कार्यक्रम में विशेष रूप से राष्ट्रीय विद्यालय समिति के अध्यक्ष अजय तिवारी, उपाध्यक्ष मदन लाल तालेड़ा, सचिव अनिल गुप्ता एवं गोकुल दास डागा, श्रीरूप चंद, श्री माल, राजकिशोर नत्थानी, अशासकीय महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष डा सुरेश शुक्ला, महाविद्यालय की प्राचार्य डा. श्रीमती संगीता घई के अलावा अन्य प्राध्यापक गण उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलन करने के साथ हुई।

मुख्य अतिथि श्री शर्मा ने महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शिनी का अवलोकन भी किया और राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता छात्राओं को पुरस्कृत भी किया।

महाविद्यालय के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं का सम्मान

कॉलेज के वार्षिकोत्सव में छात्र-छात्राओं का दिखा उत्साह

जांजगीर। जांजगीर के शासकीय टीसीएल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वरिष्ठ पत्रकार कुंजबिहारी साहू की स्मृति में छात्र-छात्राओं का सम्मान किया गया। साथ ही, कॉलेज प्रबंधन के द्वारा भी विभिन्न विधा में प्रतियोगिता के तहत छात्र-छात्राओं का सम्मान किया गया। सम्मान के बाद छात्र-छात्राओं में काफी उत्साह दिखा। इस दौरान वार्षिकोत्सव का भी आयोजन किया गया, जहां छात्र-छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी और खूब तालियां बटोरी। प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. एसडी झा थे। यहां अतिथि के रूप में प्रकाश इंडस्ट्रीज चाम्पा के वाइस प्रेसीडेंट उदय सिंह, वेलफेयर ऑफिसर राजू यादव, लॉ ऑफिसर विनय कुमार दास, विनय कुमार बाजपेयी, शासकीय नवीन महाविद्यालय नवागढ़ के प्राचार्य डॉ. बीके पटेल, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य मुरलीधर चन्द्रम मौजूद थे।

वार्षिकोत्सव के पहले कॉलेज के विभिन्न 22 कक्षाओं में प्रथम स्थान हासिल करने

वाले छात्र-छात्राओं का सम्मान, वरिष्ठ पत्रकार कुंजबिहारी साहू की स्मृति में किया गया, जिसके बाद छात्र-छात्राओं में खुशी दिखी, वहीं अतिथियों ने भी प्रतिभा सम्मान के आयोजन की सराहना की। साथ ही, कॉलेज प्रबंधन ने भी प्रतिभावान छात्र-छात्राओं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं का सम्मान अतिथियों के हाथों कराया। प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के सम्मान के बाद अतिथियों को भी वरिष्ठ पत्रकार कुंजबिहारी साहू की स्मृति में आयोजन संयोजक पत्रकार राजकुमार साहू के द्वारा प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया।

इस मौके पर मुख्य अतिथि कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. एसडी झा ने कहा कि सम्मान मिलने से छात्र-छात्राओं का उत्साह बढ़ेगा, वहीं अन्य छात्राओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि आयोजन करने वाली समिति तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि यह एक अच्छी परंपरा है, जिसकी शुरुआत कॉलेज में शुरू हुई है। डॉ. झा ने कहा कि शिक्षा से ही उत्तरोत्तर विकास होता है। ऐसे में शिक्षा क्षेत्र की प्रतिभाओं का सम्मान सभी के लिए अनुकरणीय है।

प्रकाश इंडस्ट्रीज चाम्पा के वाइस प्रेसीडेंट उदय सिंह ने कहा कि प्रतिभाओं के सम्मान से अच्छा सन्देश छात्र-छात्राओं के मध्य गया है। वरिष्ठ पत्रकार कुंजबिहारी साहू के व्यक्तित्व से वे परिचित थे। आज इस आयोजन में शामिल होने पर बड़ी खुशी हुई है और गौरव महसूस हुआ है।

किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य मुरलीधर चन्द्रम ने कहा कि ऐसे आयोजन होने से प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलता है। प्रतिभा सम्मान के साथ वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ है, जिससे प्रतिभाओं को आगे बढ़ने की सीख मिलती है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार कुंजबिहारी साहू की स्मृति में छात्र-छात्राओं का सम्मान हुआ है, इस सम्मान से छात्र-छात्राओं में बड़ी खुशी दिखी है, इससे उन्हें आगे बढ़ने प्रोत्साहन मिला है।

प्रकाश इंडस्ट्रीज के वेलफेयर ऑफिसर राजू यादव ने कहा कि वे खुद कॉलेज के छात्र रहे हैं, इसलिए, इस आयोजन में आकर बड़ी खुशी हुई है और छात्र-छात्राओं में आयोजन को लेकर भी उत्साह दिखा है, यह आयोजन की सफलता की सार्थकता को प्रदर्शित करता है। शासकीय नवीन महाविद्यालय नवागढ़ के प्राचार्य डॉ. बीके पटेल ने कहा कि पत्रकार राजकुमार साहू ने मिसाल पेश की है। उनके द्वारा अपने बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार कुंजबिहारी साहू की स्मृति में कॉलेज के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं का सम्मान किया है, यह सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से महाविद्यालय के सैकड़ों छात्र-छात्राओं में अच्छा सन्देश गया है और वे बेहतर शिक्षा के तत्पर होंगे।

मीडिया से चर्चा में शासकीय टीसीएल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एपी वर्मा ने कहा कि प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार कुंजबिहारी साहू की स्मृति में प्रतिभावान कॉलेज के 22 छात्र-छात्राओं का सम्मान किया गया, यह सराहनीय प्रयास है, जो उनके छोटे भाई पत्रकार राजकुमार साहू के माध्यम से किया गया। इस आयोजन से छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक दिशा में और आगे अग्रसर होने प्रोत्साहन मिलेगा।

आने वाले समय में भारत ही सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा- मेघवाल

केंद्रीय मंत्री ने बुद्धिजीवी वर्ग को किया संबोधित

रायपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक निजी होटल में आयोजित सम्मेलन में बुद्धिजीवी वर्ग को संबोधित किया। उन्होंने कहा कोविड के बाद कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाए चौपट हो गई, उनकी जीडीपी एक या दो प्रतिशत ही रह गई परंतु भारत पूरे विश्व में सबसे तेज गति से विकास करने वादा देश बन गया है। आने वाले समय में अमेरिका और चाइना के बाद भारत ही सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि जीडीपी में ग्रोथ के लिए खपत एक बहुत प्रमुख हिस्सा होता है प्रधानमंत्री आवास जैसी कई योजनाएं देश की खपत को बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास बनने से सीमेंट,रेत ईट,बिकेगा लोगों को मजदूरी मिलेगी, रंग रोगन के सामान इस्तेमाल होंगे ,घर बनने के बाद लोग टीवी , फ्रीज भी खरीदेंगे, ये ऐसी योजनाएं हैं जिससे एक साथ कई वस्तुओ की खपत बढ़ती है। हर वर्ग के लोगो को इससे फायदा मिलता है। मोदी सरकार देश के हर वर्ग के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है । अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है पेरोल के लिए एप्लीकेशन देना चाहता है या अदालत में जमानत के लिए अप्लाई करना चाहता है और आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण ऐसा नही कर पा रहा है तो सरकार उसकी मदद करेगी ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है।

तकनीक में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं अन्य देशो पर आश्रित नहीं होना है इसीलिए 5जी के लिए 100 लैब्स की स्थापना की घोषणा भी की गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में 20 लाख करोड़ का निवेश किया जाना है, आधारभूत संरचना के लिए 10 लाख करोड का। इन सब योजनाओ से देश में वस्तुओ की डिमांड और खपत बढ़ेगी। मिडिल क्लास व्यक्ति को 7 लाख तक टैक्स में जो छूट दी गई है टैक्स की राशि में जाने वाली इस रकम को वह कही न कही खर्च करेगा उससे फिर डिमांड और खपत बढ़ेगी।

उन्होंने बताया पहले देश के बजट को प्राथमिकता में नहीं लिया जाता था और शाम 5ः00 बजे प्रस्तुत किया जाता रहा। अटल जी की सरकार ने इसके समय को बदला और 11ः00 बजे बजट प्रस्तुत होने लगा। मा. मोदी जी ने 28 से 29 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले बजट को 1 फरवरी को प्रस्तुत करवाना शुरू किया, ताकि बजट में जो प्रावधान किए जाते है उन्हे समय से खर्च किया जा सके। पहले की सरकारें बजट को पास कराने में काफी समय लगाती थी देर से खर्च करना शुरु करती थी एवं वर्ष के अंतिम समय में बिना सोचे समझे कहीं भी खर्च करती थी अब सब कुछ प्लानिंग से होता है यह भी एक इकोनॉमिक

राज्य के मुख्यमंत्री को बताना चाहिए केंद्र कितना पैसा दे रहा है-मेघवाल

केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संवाददाता सम्मेलन में आम बजट की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह देश को ग्लोबल लीडर बनाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भ्रम फैला रहे हैं। उन्हें मनमोहन सरकार के मनरेगा के बजट एस्टिमेट्स और केंद्र की मोदी सरकार के बजट एस्टिमेट्स के आंकड़े स्टडी करके जनता के सामने रखने चाहिए मोदी सरकार का बजट एस्टिमेट बहुत ज्यादा है एवं डिमांड बढ़ने पर सप्लीमेंट्री बजट में और भी प्रावधान किए जा सकते हैं क्योंकि मनरेगा डिमांड ड्रिवन स्कीम है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास संबंधी सवाल पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मनमोहन सिंह ने कमेटी बनाई थी। योजनाओं में केंद्र राज्य के अंश का विषय संसद में आया था। कुछ योजनाएं 50-50 में, कुछ योजनाओं में 60 -40 है। मनमोहन सिंह जी ने कमेटी बनाई थी। जिसमें कई राज्यों के कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी थे जो तय किया गया था, उसी के आधार पर केंद्र की योजनाओं में राज्य और केंद्र का अंश तय हुआ है। छत्तीसगढ़ की योजनाओं और राज्य की उपेक्षा संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि यहां के मुख्यमंत्री जनता के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना उनकी है, फसल बीमा योजना भी उनकी है? हम 20 लाख करोड़ कृषि को देंगे तो यही के किसानों को सोसायटी के जरिए मिलेगा। केंद्र राज्य के बीच में प्रदेश के पिसने के सवाल पर उन्होंने कहा केंद्र भरपूर मदद कर रहा है कई बार राज्य उसे लागू नहीं करता इसीलिए केंद्र लोगों के खाते में सीधा बेनिफिट पहुंचाने की स्कीम भी लाया है किसान सम्मान निधि और फसल बीमा का पैसा सीधे खाते में जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की 30 से ज्यादा स्टेशनों का चुनाव किया गया है जिसमें प्रति स्टेशन ?15 करोड़ खर्च कर उसे एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। स्टेशनों में यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ साथ स्टेशनों का आधुनिकरण भी किया जाएगा।

मेरी बात

✍ गिरीश पंकज

लिटफेस्ट के बरक्स साहित्य महोत्सव

पिछले कुछ वर्षों से देश में लिट्फेस्ट का प्रचलन बढ़ा है। लिट्फेस्ट यानी लिटरेचर फेस्टिवल। इसके उच्चारण में भी अभिजात्य वर्ग को तकलीफ होती है इसलिए इसे वह लिट्फेस्ट कहकर संबोधित करता है। अब यह बात किसी से छिपी नहीं है कि जो तथाकथित लिट्फेस्ट हैं, वे अभिजात्य वर्ग का शगल बनते जा रहे हैं। ज्यादातर मामले में उनके आयोजकों का साहित्य से कोई खास लेना-देना नहीं होता। यही कारण है की लिट्फेस्ट में साहित्य पर गंभीर बात नहीं होती। वहां बॉलीवुड के कुछ लोकप्रिय चेहरे भीड़ एकत्र करने के लिए बुलाए जाते हैं। कुछ अन्य क्षेत्रों के भी चर्चित चेहरे भीड़ जमा करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फूहड़ विवाद पैदा करने के लिए कोई सनसनीखेज बयान देकर भी पतली गली से निकल लेते हैं। वहां आने वाले लेखक और लेखिकाओं में ज्यादातर खा-पीकर अघाए लोगों का वर्चस्व दिखाई देता है, जो केवल साहित्य-साहित्य खेलते हैं। इनके लिए कला केवल कला के लिए होती है जबकि कला जीवन के लिए हो तो उसकी उपादेयता और अधिक बढ़ जाती है। लिट्फेस्ट में आने वाले अनेक लेखक साहित्य को जीते ही नहीं, उसे अपनी छवि चमकाने का साधन समझते हैं। वहाँ शामिल लेखिकाओं को देखो तो लगता है ये किसी फैशन परेड में शामिल होने आई हुई हैं। साहित्य की सादगी, व्यवहार की शालीनता उनमें नजर नहीं आती। लिट् फेस्ट में साधक किस्म के लेखक नहीं पहुंच पाते। उनको बुलाया ही नहीं जाता। लिट्फेस्ट में शामिल होने वाले लोग अभिजात्य संस्कृति के हिस्से होते हैं। जो हवाई यात्रा से नीचे बात नहीं करते। जिन्हें पंचतारा होटल में रुकना अच्छा लगता है। जिन्हें हिंदी से नहीं, अँग्रेज़ी से प्यार होता है। ये लोग हिंदी साहित्य की भी चर्चा अँग्रेज़ी में करते हैं। इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन यह अच्छी बात है कि अब लिट्फेस्ट के बरक्स विशुद्ध साहित्य विमर्श के लिए कुछ शहरों में साहित्य महोत्सव भी होने लगे हैं। कुछ महीने पहले ऐसा ही एक महोत्सव झांसी में हुआ था, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। इसी कड़ी में 3-4 और 5 फरवरी,2023 को बनारस में काशी वाराणसी विरासत फाउंडेशन की ओर से आयोजित काशी-वाराणसी साहित्य महोत्सव का पहली बार आयोजन किया गया। यह आयोजन किसी पंचतारा होटल में नहीं हुआ। वरन तीन महत्वपूर्ण केंद्रों में हुआ। पहले दिन काशी विश्वनाथ कारिडोर में बने भव्य सभा भवन में संगोष्ठी हुई। दूसरे दिन नागरी नाटक मंडली, कबीर चौरा में आयोजन हुआ और तीसरे दिन कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली लमही में महोत्सव का समापन हुआ। साहित्य, संस्कृति और समाज पर केंद्रित इस महोत्सव में तीनों दिन ज्ञानोपयोगी अकादमिक सेमिनार हुए। जिसमें तेरह राज्यों से आए प्रतिभागी सम्मिलित हुए। आयोजन को अखबारों ने भी महत्व प्रदान किया। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि आयोजन बनारस में हुआ इसलिए दक्षिण भारत से भी अनेक ऐसे लेखक इसमें शामिल हुए, जो वहां रहकर हिंदी में लेखन कर रहे हैं। दक्षिण से आने वाले लेखकों में एक मोह काशी दर्शन का भी था। लगभग सभी लेखकों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, गंगा स्नान किया और गंगा आरती में शामिल होने का सौभाग्य हासिल किया। काशी के साथ वाराणसी शब्द का प्रयोग महोत्सव के लिए क्यों किया गया,इसको स्पष्ट करते हुए एक प्रमुख आयोजक वरिष्ठ पत्रकार राममोहन पाठक ने बताया कि काशी राशि तो हमारी हजारों साल पुरानी नगरी है, मगर वाराणसी का नामकरण बहुत बाद में हुआ इसलिए हमने प्राचीन और अर्वाचीन को जोड़कर इसे काशी वाराणसी साहित्य महोत्सव नाम दिया। सांसद और लेखक आर के सिन्हा के प्रयासों से यह महोत्सव शुरू हुआ, जिसमें कमलेश दत्त कमल, जितेंद्रनाथ मिश्र नरेंद्र नाथ मिश्र सहित काशी के अनेक सृजन धर्मी दलितों के उद्धार जुड़े हुए थे। पहली बार आयोजन हुआ इसलिए व्यवस्था संबंधी कुछ कमियां जरूर नजर आई, मगर साहित्य महोत्सव का जो विराट लक्ष्य था, वह सार्थक हुआ। महोत्सव में केवल हिंदी साहित्य की चर्चा नहीं हुई, वरन विश्व साहित्य का संस्पर्श करते हुए भारतीय साहित्य में क्या लिखा जा रहा है, इसके बारे में विचार विमर्श हुआ। विभिन्न वक्ताओं ने अपने सार्थक विचार व्यक्त किए। भारतीय भाषाओं के अनेक मनीषियों का उल्लेख करते हुए मैंने और कुछ वक्ताओं ने इस बात को सिद्ध किया कि रचना किसी भी भाषा में हो रही हो, मगर उन सब का एक ही लक्ष्य रहा है, लोकमंगल की कामना और मनुष्य की सोई हुई करुणा को जगाना। अगर बनारस में कबीर रविदास जैसे लेखक अपनी रचनाओं के माध्यम से पुनर्जागरण कर रहे थे, तो उधर केरल में श्रीनारायण गुरु भी दलितों के उद्धार के लिए समाज को जगा रहे थे। जैसे महाराष्ट्र में संत रामदेव, तुकाराम, सन्त ज्ञानेश्वर, रामदास जैसे संत अपनी रचनाओं के माध्यम से मानव समाज को परिमार्जित कर रहे थे। काशी वाराणसी साहित्य महोत्सव विशेष रूप से भारतीयता के निकष पर खरा उतरा और सबसे बड़ी बात यह है लिट्फेस्ट की तथाकथित अभिजात्य परंपरा के विरुद्ध महोत्सव एक रचनात्मक हस्तक्षेप लगा। साहित्य में जो सहित का भाव है, सबके हित की चिंता है, वह विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से उभर कर सामने आया। मुझे लगता है, अगर भारतीय साहित्य को राष्ट्रीयता से जोड़कर रचने की जरूरत है तो इसी तरह के साहित्य महोत्सव होने चाहिए । लिट्फेस्ट, जहां लेखन को साधना मानकर जीने वाले लेखक नजर नहीं आते, वरन वहाँ ऐसे सुविधाभोगी अघाए लेखकों की भरमार रहती है,जो सिगरेट और शराब के शौकीन होते हैं। जिन्हें लिव इन रिलेशनशिप अच्छी लगती है, जो समलैंगिकता की वकालत करते हैं, और वक्त आने पर अपने देश को भी गाली देने से परहेज नहीं करते। साहित्य की ऐसी अराजक पीढ़ी को ज़वाब देने के लिए काशी- वाराणसी साहित्य महोत्सव जैसे आयोजनों को प्रोत्साहित किया जाना अति आवश्यक है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साव ने दी नीलकंठ ककेम को श्रद्धांजलि

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने बीजापुर में मंडल अध्यक्ष नीलकंठ ककेम की नक्सलियों द्वारा हत्या पर गहन शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि स्वर्गीय नीलकंठ ककेम भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता होने के साथ ही सक्रियता के साथ समाजसेवा कर रहे थे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता के रूप में सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है।

भाजपा की बैठकों में बन रही चुनाव की कार्ययोजना

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की आज हुई विभिन्न बैठकों की जानकारी देते हुए प्रदेश भाजपा महामंत्री विजय शर्मा ने बताया कि भाजपा कोर ग्रुप के साथ, छत्तीसगढ़ बचाओ कांग्रेस भगाओ अभियान की टीम की एक बड़ी बैठक संपन्न हुई जिसमें प्रदेश भर के सभी लोकसभा क्षेत्रों में प्रवास के बाद का फीडबैक प्रस्तुत किया गया। लोकसभा प्रवास की तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ चर्चा हुई , सभी विधानसभा क्षेत्रों से यह बात पुष्ट हुई कि, पूरे प्रदेश में कांग्रेस की भ्रष्ट, अराजक और वादाखिलाफी करने वाली सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर आक्रोश है संभाग प्रभारियों और महामंत्रियों की बैठक भी हुई,जिसमे आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई व संभाग प्रभारियों ने अपने संभाग की विस्तृत जानकारी दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साव और महामंत्रियों की भी बैठक हुई। जिसमे आगे की रणनीति तय की गई।

प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने बताया कि कल सभी मोर्चों की प्रदेश कार्यसमिति बैठक भी होगी। मोर्चों की कार्यसमिति की बैठक के उद्घाटन सत्र में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रहेंगे।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

एम्स में नेशनल योगा एनाटॉमी वर्कशॉप में शामिल हुए ज्ञानेश शर्मा

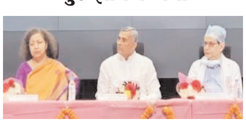

रायपुर। ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सांइस रायपुर द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार नेशनल योगा एनाटॉमी वर्कशॉप में योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वर्कशॉप का उद्घाटन एम्स रायपुर के डायरेक्टर एवं सीईओ डॉ. नीतिन एम नागरकर ने किया। इस सेमिनार में देश विदेश से आए लगभग अस्सी योग साधक और विशेषज्ञों ने भाग लिया। सेमिनार में शरीर की संरचना और उसके विभिन्न अंगों के बीच पारस्परिक संबंधों पर बारीकियों से विश्लेषण किया गया। ज्ञानेश शर्मा ने सेमिनार में योग के महत्व के साथ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोगों में योग और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आयुष मंत्रालय नई दिल्ली से डॉ. वादिराज, छत्तीसगढ़ योग आयोग के सचिव एम. एल. पाण्डेय सहित संस्थान के डॉक्टर उपस्थित थे।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा तीन सवाल

रायपुर। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से अडानी के घोटाले के संबंध में तीन सवाल पूछा? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से देश की जनता तीन सवालों का जवाब जानना चाहती है। मोदी जवाब दें कि आईडीबीआई बैंक, न्यू इंडिया एश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जैसे असफल विनिवेशों से उबारने के लिए एलआईसी निधियों का उपयोग करने के संबंध में आपकी सरकार का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसी परिस्थितियों से उबारना एक बात है, लेकिन अपने पूंजीपति दोस्तों को और अमीर बनाने के लिए 30 करोड़ वफादार पॉलिसी-धारकों की बचत का उपयोग करना दूसरी बात है। अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी और धन-शोधन के आरोप कुछ समय से सार्वजनिक पटल पर हैं। अडानी समूह में प्रमुख फंडो के निवेश के वास्तविक लाभार्थी कौन हैं, इस संबंध में अनेक सवाल उठते रहे हैं। हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद पहली बिकवाली मेंएलआईसी द्वारा खरीदे गए अडानी समूह के शेयरों का मूल्य 32,000 करोड़ गिर गया, जिससे एलआईसी की स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार 27 जनवरी 2023 को उसके शेयरों का मूल्य 56,142 करोड़ रह गया। तब से अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर के कई शेयरों में 50 प्रतिशत की और गिरावट आई है।

' भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है कांग्रेसराज में: नेताम

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री रामविचार नेताम ने बस्तर के बीजापुर और सुकमा इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या तथा संदिग्ध मौत पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि गुंडागर्दी और कांग्रेस के कुशासन की वजह से पूरे राज्य में हालात बिगड़ गए हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजापुर में भाजपा के मंडल अध्यक्ष नीलकंठ की हत्या कर दी गई। इसके पहले भाजपा के कार्यकर्ता किलेपाल के पूर्व सरपंच की लाश संदिग्ध हालत में मिली। कई भाजपा के पदाधिकारियों को बेवजह जेल में बंद कर दिया गया है उन पर गलत धाराएं लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। यह बेहद गंभीर बात है लोगों की जमीन और मकान पर अवैध कब्जा हो रहा है। किसी की जमीन किसी के नाम की जा रही है। किसी के मकान पर तख्ती लगाई जा रही है कि अब वह मकान उसका नहीं रहा। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जमीनों के रिकॉर्ड में हेराफेरी की जा रही है। मरे हुए लोगों को जिंदा बताकर उनकी जमीन हड़पी जा रही है। बलरामपुर जिले में ऐसा हुआ है और बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में यह खेल चल रहा है।

रमन सिंह किस हैसियत से राजभवन की तरफ से बयान दे रहे-कांग्रेस

रायपुर। बिलासपुर उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण मसले पर राज्यपाल को भेजे गए नोटिस के मामले में रमन सिंह द्वारा यह बयान दिया जाना कि "नोटिस का जवाब दे दिया जायेगा" बेहद ही आपत्तिजनक बयान है। रमन सिंह बताएं कि वह किस हैसियत से उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल को भेजे गए नोटिस के संबंध में टिप्पणी कर रहे हैं? उच्च न्यायालय ने नोटिस राजभवन को भेजा है जवाब राजभवन की तरफ से आना चाहिए, भाजपा नेता क्यों और कैसे जवाब दे रहे यह इस बात का प्रमाण है कि आरक्षण मामले में राजभवन, भाजपा के सुर एक है। अदालत का फैसला आये बिना रमन सिंह का यह कहा जाना कि जब 58 प्रतिशत आरक्षण अदालत में नहीं टिका तो 76 प्रतिशत कैसे टिकेगा यह रमन सिंह की दुर्भावना को प्रदर्शित करता है। रमन सिंह नहीं चाहते कि 76 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक कानून बने इसीलिये वे इस पर बिना किसी आधार के टिप्पणी करके भ्रम का वातावरण बनाने में लगे है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के निजी राजनैतिक स्वार्थ के कारण आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में रुका हुआ है।

कवासी लखमा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के दबाव में हैं- केदार

रायपुर। प्रदेश भाजपा महामंत्री तथा छत्तीसगढ़ के पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा द्वारा आदिवासियों के हिंदुओं से अलग होने के संदर्भ में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ वातावरण बना रहे हैं।यह साजिश उनके शीर्ष नेतृत्व द्वारा कराई जा रही है। इसके मूल में आदिवासी संस्कृति को खत्म कर धर्मांतरण कराकर आदिवासियों को ईसाई बनाने की सुनियोजित साजिश है। प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बारसूर में गणेश जी की प्राचीनतम प्रतिमा है। हम आदिवासी गणेश जी की पूजा करते हैं। इसी तरह दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माई की हम आदिवासी पूजा करते हैं। हजारों वर्षों से दंतेश्वरी माई बस्तर की आराध्य देवी हैं। कवासी लखमा जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहां इंजरम में भगवान राम आए थे। प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सोनिया गांधी ईसाई हैं और सनातन संस्कृति के खिलाफ कांग्रेस नेताओं से अपनी बात कहलवा रही हैं। उन्होंने कहा कि कवासी लखमा आदिवासियों को हिंदुओं के विरोध में बताते हैं। उन्हें ईसाइयों के विरोध में क्यों नहीं बताते? धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के दबाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है।

पुरानी पेंशन बहाली योजना अब विकल्प से नई टेंशन योजना बनी

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में भूपेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर प्रदेश के पुरानी पेंशन के मांग कर रहे कर्मचारियों का दिल जीत लिया,परंतु शासन ने पुरानी पेंशन बहाली योजना में विकल्प का पेंच डालकर कर्मचारियों को असमंजस में डाल दिया है,वे इस सोच में है, करे तो क्या करें, इसी बीच अब पेंशन संचालनालय ने एक फरमान जारी कर पुरानी पेंशन चाहने वालों को 24 फरवरी, 23 तक विकल्प देने का समय सीमा निर्धारित कर सोचने- समझने के अवसर को समाप्त कर दिया है और पुरानी पेंशन योजना को नई टेंशन योजना बना दिया है। जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री व छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल को ट्वीट करके विकल्प और एफिड़ेविट लेने की प्रक्रिया को तुरन्त रोक रद्द करने की मांग की है।छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना छत्तीसगढ़ राज्य में लागू कर केन्द्र सरकार व मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन लागू करने के दबाव में ला दिया,परंतु इसे लागू करने में तरह तरह के पेंच डालने से सरकार की मंशा पर अब सबको शंका होने लगी है। क्योंकि पुरानी पेंशन योजना या नई पेंशन योजना? इस पर कर्मचारियों को इसी महीने अपना विकल्प पत्र जमा करना होगा। पेंशन डायरेक्ट्रेट की तरफ से सभी ट्रेजरी ऑफिसर को निर्देश जारी कर दिया गया है,जारी आदेश के मुताबिक 1.11.2004 से 31.3.2022 के बीच नियुक्त हुए कर्मचारी एनपीएस और ओपीएस का अपना विकल्प पत्र भरकर 24 फरवरी तक जमा करना होगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वोरा ने जताया आभार

चिटफंड कंपनियों में निवेश 2 करोड़ 56 लाख रुपए लौटाए गए

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के 3 हजार 274 निवेशकों को आज 2 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि वापस लौटाई है। सीएम हाऊस में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले दुर्ग जिले के निवेशकों को यह रकम लौटाई गई। आज हुए वर्चुअल कार्यक्रम में दुर्ग कलेक्टोरेट सभागार में विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा, एसपी अभिषेक पल्लव सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। दुर्ग जिले में अब तक चिटफंड कंपनियों के 126 डायरेक्टर और 8 पदाधिकारियों की गिरफ्तार किया गया है। जबकि पूरे प्रदेश में निवेशकों को लगभग 40 करोड़ रुपए की राशि लौटाई गई है। चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में कठोर कार्रवाई की जा रही है। ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों की सम्पत्तियों को कुर्क कर निवेशकों को राशि वापस की जा रही है। आज शुष्क इंडिया लिमिटेड कंपनी उज्जैन की संपत्तियों की नीलामी से प्राप्त राशि 2.56 करोड़ रूपये का 3274 निवेशकों को वितरण किया गया। दुर्ग जिले में कुल 314 चिट फंड कंपनियों में 1,35,718 निवेशकों ने 4 अरब 32 करोड़ 38 लाख रुपये का निवेश किया है। इन 314 कंपनियों की प्रशासन द्वारा जांच की गई है। 228 कंपनियों के विरूद्ध एफ.आई.आर के लिए पुलिस को प्रेषित किया जा चुका है। 62 एफ. आई. आर. दर्ज की जा चुकी है, जिसमें निवेशकों की लगभग 58 करोड़ की राशि शामिल है।

दुर्ग के विधायक अरुण वोरा ने आज कलेक्टोरेट में मौजूद निवेशकों को राशि वापस मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशील और सजग पहल के कारण ही निवेशकों को रकम वापस मिल रही है। पूरे देश में केवल छत्तीसगढ़ में ही चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए निवेशकों को रकम वापस की जा रही है। वोरा ने इसके लिए मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए निवेशकों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस दौरान निवेशकों ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर उन्हें पूरा भरोसा है। चिटफंड कंपनियों से सभी निवेशकों को पूरी राशि मिलेगी।

पुलिस द्वारा अभी तक 62 प्रकरणों में 126 डायरेक्टर और 8 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। जनवरी 2023 में विराट क्रेडिट को-आपरेटिव कंपनी के 8 डायरेक्टर गिरफ्तार किए गए। जिले में कुर्की / राजीनामा से 23.91 लाख में से 21.94 लाख रूपये की राशि कोलकाता बीयर एंड लिमिटेड कम्पनी से निवेशकों को वापिस कराई गई है। संजय इंफ्रा लिमिटेड से 17 निवेशकों की राजीनामा के तहत् 11.90 लाख रुपये की राशि वापस कराई गई है।

आर.एन.आई. रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.